

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट पिटिशन नम्बर 631 वर्ष 2017 (एम/एस)

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं० लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 187 वर्ष 2016 (एम/एस)

टी.एच.डी.सी. इंडिया लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 272 वर्ष 2016 (एम/एस)

नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 1500 वर्ष 2016 (एम/एस)

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं० लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 2074 वर्ष 2016 (एम/एस)

एम/एस स्वस्ती पावर प्राइवेट लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 3084 वर्ष 2016 (एम/एस)

एम/एस भिलंगना हाइड्रो पावर लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 123 वर्ष 2017 (एम/एस)

एम/एस जयप्रकाश पावर वैन्चोर्स लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 641 वर्ष 2018 (एम/एस)

एम/एस स्वास्ती पावर प्राइवेट लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 2396 वर्ष 2019 (एम/एस)

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं० लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 3603 वर्ष 2019 (एम/एस)

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं० लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

साथ में

रिट पिटिशन नम्बर 279 वर्ष 2020 (एम/एस)

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं० लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

श्री वी०के० कोहली, श्री मोहन पारासरण, श्री गौरब बनर्जी, श्री अरविन्द वशिष्ठ, श्री डी० एस० पाटनी वरिष्ठ अधिवक्तागण, श्री दिव्याकान्त लाहोती, श्री आलोक मेहरा, श्री शोभित सहारिया, याचीगण के अधिवक्ता।

श्री दिनेश द्विवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ० अभिषेक अत्रे, श्री प्रतीक द्विवेदी, श्री शिवम सिंह, श्रीमती अंजली भारवावा, श्री पी० सी० बिष्ट, एडिशनल चीफ स्टेंडिंग काउंसिल और श्री नरैन दत्त, राज्य के ब्रीफ होल्डर।

श्री आदित्य सिंह, याची एम/एस भिलंगना हाइड्रो पावर लि० के अधिवक्ता।

श्री गोपाल के. वर्मा एडिशनल सी.एस.सी. राज्य उत्तर प्रदेश।

श्री राजेश शर्मा एवं श्री संजय भट्ट, यूनियन ऑफ इंडिया के स्टेंडिंग काउंसिल।

श्री यू०के० उनियाल वशिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री जितेन्द्र चौधरी, यूपीपीसीएल के अधिवक्ता।

उद्धृत मामलों की कालानुक्रमिक सूची –

1. (2017) 12 एस०सी०सी० 1, जिन्दल स्टेनलैस लि० व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य।
2. (2010) 6 एस०सी०सी० 449 गोवा ग्लास फाइबर लि० बनाम गोवा राज्य व अन्य।

3. (2010) 12 एस0सी0सी0 1, भानुमति व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
4. (2005) 8 एस0सी0सी0 334, गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात।
5. (2004) 1 एस0सी0सी0 712, धर्मदत्त बनाम भारत संघ।
6. (2004) 2 एस0सी0सी0 249, एम0पी0 सीमेण्ट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य।
7. (2004) 6 एस0सी0सी0 465, पंजाब राज्य बनाम नेश्ले इंडिया लि0 व अन्य।
8. (2004) 10 एस0सी0सी0 201, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कैशोराम इंडस्ट्रीज लि0 व अन्य।
9. (2001) 3 एस0सी0सी0 654, म्यूनिसिपल काउंसिल कोटा बनाम दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कंपनी लि0।
10. (1997) 2 एस0सी0सी0 42, इच्छापुर इंडस्ट्रीयल कोऑपरेटिव सोसायटी लि0 बनाम कम्पेटेन्ट अथॉरिटी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन।
11. (1997) 2 एस0सी0सी0 453, बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टीलेरी लि0
12. (1996) 3 एस0सी0सी0 709, आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य बनाम मैकडॉवेल एण्ड कंपनी व अन्य।
13. (1995) 1 एस0सी0सी0 274, कसिन्का ट्रेडिंग व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य।
14. 1993 सुप्र (1) एस0सी0सी0 96 (प्) कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के मामले में
15. (1992) 2 एस0सी0सी0 411, अमृत बनस्पति कंपनी लि0 व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य।
16. (1990) 1 एस0सी0सी0 12, इंडिया सीमेण्ट्स लि0 व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य।

17. (1990) 1 एस0सी0सी0 109, सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
18. (1983) 4 एस0सी0सी0 45, फार्मास्यूटिकल्स लि0 व अन्य बनाम बिहार राज्य।
19. (1969) 2 एस0सी0सी0 55, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ अरबन लैंड टैक्स बनाम बकिंघम और कर्नाटक कंपनी लि0।
20. ए0आई0आर0 1967 एस0सी0 55, फर्म बंशीधर प्रीसुखदास बनाम राजस्थान राज्य
21. 1965 2 आन्ध्रा लॉ टाइम्स 297, एन0 आर0 रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य।
22. ए0आई0आर0 1953 एस0सी0 375, के0 सी0 गजपति नारायण देव व अन्य बनाम ओडिशा राज्य।

माननीय लोक पाल सिंह, जज

- 1^ण चूंकि उपरोक्त रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून का मुद्दा समान है, इसलिये संक्षिप्ता और सुविधा के लिये सभी याचिकाओं का निस्तारण इस निर्णय द्वारा किया जा रहा है।
- 2^ण रिट याचिका संख्या 1500 वर्ष 2016 (एम/एस) अग्रणी मामला रहेगा।
- 3^ण याचिकाओं के वर्तमान समूह में याचिकाकर्ता बिजली उत्पादन कंपनियां है, जो नदी के पानी का उपयोग करके बिजली के उत्पादन में लगी हुई हैं। याचिकाकर्ता, अलकनन्दा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएयपीसीएल) अन्य बातों के अलावा, बिजली उत्पादन अधिनियम, 2012 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) पर उत्तराखण्ड जल कर की संवैधानिक वैधता और अधिकारों पर निम्नलिखित आधारों पर हमला करना चाहती है—

(1) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और

अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200, 246, 248, 256, 285, 288(2) और 300ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(2) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 1 की प्रविष्टि 97 के प्रावधान का उल्लंघन है।

(3) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 2 की प्रविष्टि 17 के प्रावधान का उल्लंघन है।

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 288(2) का उल्लंघन होने के कारण उक्त अधिनियम के अधिनियमन पर विचार कर दी गयी सहमति, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

(5) प्रतिवादी संख्या 01-05 द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसार जल कर की दरों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 288(2) का उल्लंघन है, क्योंकि उक्त अधिनियम भारत के राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त किये बिना प्राख्यापित किया गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 288(2) के तहत अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। जिसमें राज्य विधानमण्डल की ओर से किसी प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर की किसी भी दर और अन्य घटनाओं के निर्धारण के मामले में कानून पूर्व सहमति के लिये प्रदान करेगा। राष्ट्रपति को ऐसे किसी नियम या आदेश को बनाने के लिये कहा जा रहा है। जल कर की दरों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(6) उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जल कर लगाने का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता

को अपना व्यापार और व्यवसाय जारी रखने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

(7) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना मनमाना है, राज्य की कार्यवाही में मनमानी प्रकट करता है और प्रतिवादी राज्य उत्तराखण्ड की रंगीन शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

4^ण वर्तमान विवाद की उत्पत्ति यह है कि वर्ष 1981 में 330 मेगावाट की क्षमता वाली श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना नामक परियोजना की परिकल्पना तत्कालीन सरकार द्वारा की गयी थी। परियोजना का विकास पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को सौंपा गया था और इसे विश्व बैंक के धन से विकसित करने की योजना बनायी थी। यह कहा गया है कि सरकार द्वारा की गयी अत्यधिक देरी के कारण परियोजना को विकसित करने में विश्व बैंक ने धन वापस ले लिया और धन की कमी के कारण सरकार ने विकास के लिये परियोजना को निजी पार्टियों को सौंपने का निर्णय लिया। टाटा पावर कॉर्पोरेश लिमिटेड (टाटा/टीपीसीएल) ने परियोजना विकास कार्यों को अपने हाथों में ले लिया जो परियोजना के विकास में प्रगति करने में सफल नहीं हो सका और अन्ततः, वर्ष 2005 में हैदराबाद के जी0वी0के0 ग्रुप ने इसे अपने हाथ में ले लिया और परियोजना विकास कार्य सौंपा। इससे पहले जब डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर लिमिटेड (डकन्स)(जिसे अब अलकनन्दा हाइड्रो पावर कंपनी लि0 के नाम से जाना जाता है) को परियोजना सौंपी गयी थी तो दोनों के बीच दिनांक 27.08.1998 को एक समझौता ज्ञापन और एक कार्यान्वयन समझौता (आईए) दर्ज किया गया था। इससे पहले पूर्ववर्ती राज्य यू0पी0 और डंकन ने परियोजना से बिजली पैदा करने के लिये अलकनन्दा नदी के पानी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिये दिनांक 28.08.1998

को एक जल उपयोग समझौते में प्रवेश किया। इस बीच वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया। पूर्ववर्ती यूपी राज्य के विभाजन के बाद परियोजना से उत्पन्न होने वाले लाभों को यूपी राज्य, उत्तराखण्ड राज्य एवं अलकनन्दा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) के बीच साझा करने की परिकल्पना की गयी थी और उक्त तीन पक्षों के बीच समझ को प्रभावी बनाने के लिये मौजूदा आईए में संशोधन किया गया और इसे पुनः स्थापित कार्यान्वयन समझौते (आरआईए) के रूप में बहाल किया गया। याचिकाकर्ता एचपीसीएल, यूपी सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आईए में संशोधन किया और प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट शब्दों में चित्रित करने के लिये दिनांक 10.02.2006 (आरआईए) को पुनः स्थापित कार्यान्वयन समझौते में प्रवेश किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परियोजना द्वारा अलकनन्दा नदी के पानी का उपयोग करने के लिये निःशुल्क और रॉयल्टी के रूप में आपूर्ति की जाने वाली 12 प्रतिशत बिजली का पहलू भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

5^ण आईआरए के खण्ड 1.65 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल उपयोग समझौता या डब्ल्यूयूए का अर्थ वह दस्तावेज है, जो 28 अगस्त, 1998 को तत्कालीन यूपी सरकार और कंपनी के बीच निष्पादित हुआ था, जिसके तहत तत्कालीन यूपी सरकार ने परियोजना के लिये विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिये अलकनन्दा नदी के पानी का उपयोग करने का कंपनी के अधिकार को मंजूरी प्रदान की थी।

6^ण आरआईए का खण्ड 13 जल उपयोग अधिकारों को परिभाषित करता है और यह प्रदान करता है कि उत्तराखण्ड सरकार इसके द्वारा कंपनी को परियोजना के लिये अलकनन्दा नदी के पानी का उपयोग करने के लिये अवधि के दौरान किसी भी और सभी शुल्क को मुक्त अधिकार देती है। साइट पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करें

और ऐसे उचित उद्देश्यों के लिये इस आरआईए की शर्तों के अनुसार और परियोजना के लिये पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के अधीन बिजली उत्पादन के लिये सीधे सम्बन्धित और आवश्यक है। ऐसा अधिकार पहले उपलब्ध था, तत्कालीन हस्ताक्षरित जल उपयोग समझौते के तहत, कंपनी जो अब आरआईए के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित हो गयी है। उत्तराखण्ड सरकार इस अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा उत्पादित किसी भी प्रकार की बिजली पर कोई कर, शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगायेगी।

70 यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त के मध्येनजर उस पानी पर कोई कर/उपकर/शुल्क आदि लागू नहीं होगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन के लिये किया जाता है। इसके अलावा आरआईए दिनांक 10.02.2006 का खण्ड 17.1 निम्नानुसार प्रदान करता है—

“17.1 कंपनी के दायित्व: परियोजना के उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पन्न सम्पूर्ण ऊर्जा को ऊर्जा आउटपुट कहा जाएगा। ऊर्जा उत्पादन और सहायक खपत के बीच के अन्तर को बिक्री योग्य ऊर्जा कहा जाएगा। बिक्री योग्य ऊर्जा की आपूर्ति कंपनी के स्विचयार्ड में 400 केवी आउटलेट गैन्ट्री पर 400 केवी इंटरकनेक्शन पावर प्वाइंट पर कंपनी द्वारा विधिवत मीटर लगाकर की जाएगी। सरकार, उत्तराखण्ड परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा का 12 प्रतिशत निःशुल्क पाने का हकदार होगा। सरकार यूपी/यीपीपीसीएल और कंपनी इस बात पर सहमत हैं कि यह 12 प्रतिशत निःशुल्क बिक्री योग्य ऊर्जा सरकार को आपूर्ति की जाएगी। कंपनी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को 12 प्रतिशत बिक्री योग्य ऊर्जा के बदले में पहले कंपनी द्वारा मुफ्त आपूर्ति की जानी थी। यूपी/यीपीएसईबी की। जीओयूपी/यूपीपीसीएल/कंपनी सरकार को 12 प्रतिशत बिक्री योग्य ऊर्जा के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तराखण्ड के श्रीनगर में कंपनी के स्विचयार्ड में 400 केवी आउटलेट गैन्ट्री पर 400 केवी इंटरकनेक्शन बिन्दुओं पर

.....”

8^० यह कहा गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2005-06 में बांध और अन्य विकास परियोजना विकास कार्यों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन वह अप्रैल, 2015 के महीने में ही काम पूरा कर सका और उसने अपनी यूनिट 1 के दिनांक 23.04.2015, यूनिट 3 दिनांक 10.05.2015 तथा यूनिट 2 एवं 4 दिनांक 20.06.2015 को वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी। इस प्रकार अप्रैल, 2015 तक परियोजना ने बिजली उत्पादन के लिये अलकनन्दा नदी के किसी भी पानी का उपयोग नहीं किया है। आगे कहा गया है कि परियोजना की शुरुआत के समय से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 (अधिनियम) के लागू होने से पहले किसी भी समय खींचे गये पानी पर कोई कर या उपकर नहीं लगाया गया था। याचिकाकर्ता जिसका उपयोग या तो निर्माण उद्देश्यों के लिये या बिजली उत्पादन के लिये किया गया था। याचिकाकर्ता पर पहले के समय में कोई कर/उपकर/रॉयल्टी नहीं लगाया गया था, सम्भवतः आरआईए के अनुपालन के कारण जो इस बात पर विचार करता है कि परियोजना से उत्पन्न 12 प्रतिशत बिजली याचिकाकर्ता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बदले में रॉयल्टी के रूप में उत्तराखण्ड राज्य को मुफ्त दी जाएगी। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.11.2015 (कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के तहत) याचिकाकर्ता को अधिनियम की घोषणा के बारे में सूचित किया गया और आगे बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में 5 मेगावाट से अधिक क्षमता (याचिकाकर्ता की तरह) की जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादन के प्रयोजनों के लिये खींचे गये पानी पर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थी। आगे तीन वर्षों के लिये बिजली की दरें इस प्रकार हैं –

क्रम संख्या	उपलब्ध हैड	जल कर की दर
1	30.00 एम तक	02 पैसे प्रति घन मीटर

2	31.00 एम से 60.00 एम	05 पैसे प्रति घन मीटर
3	61.00 एम से 90.00 एम	07 पैसे प्रति घन मीटर
4	90.00 एम से ऊपर	10 पैसे प्रति घन मीटर

9^ण इसके बाद प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा जारी एक आक्षेपित पत्र दिनांक 07.12.2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के पंजीकरण की आवश्यकता और अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये फॉर्म भरने और पंजीकरण शुल्क जमा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। आरोप है कि अचानक याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा जारी आक्षेपित पत्र दिनांक 26.04.2016 प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त अधिनियम के तहत बिजली पैदा करने के लिये पानी के कथित उपयोग के लिये 27,97,39,600/- रुपये (नवम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिये) की मांग की। अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड में जल विद्युत स्टेशनों को अधिनियम के तहत स्थापित आयोग में पंजीकरण के लिये अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, जो 15.08.2015 है और आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने का आदेश पारित करेगा। उपर्युक्त अनुभाग में आगे कहा गया है कि यदि उपयोगकर्ता निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने या पंजीकरण करने में विफल रहता है तो आयोग तुरन्त जुर्माना लगाएगा जो लंबे समय तक डिफॉल्ट के मामले में बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं 9, 10 और 12 यहां दी गयी हैं –

“9. कोई भी व्यक्ति ऐसी योजनाएं स्थापित नहीं करेगा, जिसमें पानी के उपयोग की आवश्यक हो या किसी अन्य तरीके से पानी का उपयोग किया जाए, जब तक कि वह

धारा 10 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र द्वारा ऐसा करने के लिये अधिकृत न हो।”

“10. कोई भी उपयोगकर्ता जो पानी के उपयोग करने का इरादा रखता है (गैर-उपभोग्य उपयोग) उपयोगकर्ता और आयोग के बीच समझौता अधिनियम के तहत बिजली उत्पादन के लिये एक के निष्पादन के बाद एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

“12(1) पंजीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली उत्पादन के लिये निकाले गये पानी के लिये जल कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) जहां किसी उपयोगकर्ता ने अधिनियम के शुरु होने से पहले बिजली उत्पादन के उद्देश्य से जल विद्युत योजना का निर्माण किया है, ऐसे उपयोगकर्ता को अधिनियम के शुरु होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा। अधिनियम और आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित उपयोगकर्ता उसमें निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण करने या पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो आयोग तुरन्त उपयुक्त जुर्माना लगाएगा, जिसे लंबे समय तक डिफॉल्ट के मामले में बढ़ाया जा सकता है।

10^ए अधिनियम का अध्याय 4 उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गये पानी के आकलन का वर्णन करता है।

11^ए अधिनियम की धारा 14.1 में खींचे गये पानी का आकलन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है—

“आयोग योजना के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करेगा या उपकरण

स्थापित करायेगा, जहां आयोग बिजली उत्पादन के लिये खींचे गये पानी को मापने के प्रयोजनों के लिये उपयुक्त समझे या खींचे गये पानी के आकलन के लिये कोई अप्रत्यक्ष विधि अपना सकता है।”

12^ण अधिनियम की धारा 14.2 निम्नानुसार प्रावधान करती है –

“आयोग या तो अपने परिसर में या अपने स्थान पर या आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित कर सकता है या स्थापित करने की आवश्यकता पर कर सकता है और उसके बाद ऐसे द्वारा किये गये व्यय को समायोजित कर सकता है। ऐसी स्थापना का उपयोगकर्ता को जल कर देय होगा।”

13^ण याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी ने न तो निकाले गये पानी को मापने के लिये परिसर के भीतर कोई प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित किया था और न ही उपयोग किये गये पानी की मात्रा को मापने के लिये कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया था और प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा किये गये व्यय को समायोजित करने के लिये कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं किया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना विवादित नोटिस जारी किया गया था। अधिनियम का अध्याय 5 जल कर से सम्बन्धित है। अधिनियम की धारा 17.1 निर्धारित करती है कि “उपयोगकर्ता अधिनियम के तहत ऐसी दरों पर जल कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदारी होगा जो सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है।” आगे अधिनियम की धारा 19(1) में कहा गया है कि बिजली उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गये पानी का मूल्यांकन और उसके जल कर की गणना आयोग द्वारा की जाएगी। धारा 19(2) में प्रावधान है कि उपयोगकर्ता उपधारा (1) के तहत निर्धारित जल कर का भुगतान करेगा।

14^ए यह आरोप लगाया गया है कि अधिनियम के तहत न तो कोई आयोग स्थापित किया गया था और न ही ऐसे आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा खींचे गये पानी के आधार पर कर की गणना की है, न केवल अनुपालन के अभाव में लागू नोटिस कानून की नजर में खराब है, अधिनियम की धारा 14, 17, 19 के तहत गैर रखरखाव योग्य है, क्योंकि नोटिस के तहत दावा की गयी राशि निराधार है और केवल अनुमानों पर बनायी गयी है।

15^ए याचिकाकर्ता के अनुसार, हाइड्रो स्टेशन में उत्पन्न बिजली की मात्रा जल कंडक्टर प्रणाली के प्रवेश और निकास के स्तर में अन्तर के कारण हेड के समानुपाती होती है। इसलिये हाइड्रो टरबाइनों से गुजरने वाले पानी की समान मात्रा लो हेड वाले हाइड्रो स्टेशन की तुलना में हार्ड हेड पावर स्टेशन में अधिक बिजली उत्पन्न करेगी। इस प्रकार शीर्ष के श्रेणीबद्ध पैमाने पर प्रतिघन मीटर के आधार पर पानी की मात्रा के आधार पर जल कर लगाना वास्तव में बिजली उत्पादन पर कर लगाना ही है। यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना में जल कर लगाने का प्रावधान दिया गया है, जो याचिकाकर्ता को उचित सूचना एवं अवसर दिये बिना पारित कर दिया गया। इसे अलावा रॉयल्टी के लिये याचिकाकर्ता पर जो दायित्व तय किया गया है, वह आरआईए की स्पष्ट शर्तों या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। आरआईए उत्तराखण्ड सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार एवं याचिकाकर्ता के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। इसके तहत नियम और शर्तें सरकार द्वारा एएसपीसीएल/याचिकाकर्ता पर थोपी गयी थी। आरआईए की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा कोई रॉयल्टी, कर, उपकर या कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सरकार द्वारा एक स्पष्ट छूट प्रदान की गयी है और आरआईए उत्तराखण्ड सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पर एक बाध्यकारी समझौता है। याचिकाकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना आरआईए में किया गया कोई भी बदलाव न केवल आरआईए की शर्तों का उल्लंघन होगा बल्कि सरकार का कृत्य भी होगा और

सरकार का मामला एकतरफा, मनमाना और इस प्रकार कानून के तहत अस्थिर है। यह आरोप लगाया गया है कि अधिनियम के प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होंगे और याचिकाकर्ता को कर या उपकर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। दूसरी ओर उसी आरआईए ने उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नदी के पानी के उपयोग के कारण परियोजना से 12 प्रतिशत बिजली उत्तराखण्ड राज्य को मुफ्त में प्रदान करने की परिकल्पना की है। इस प्रकार, कोई भी कर, उपकर या रॉयल्टी लगाना दोहरे कराधान के समान होगा और इस प्रकार अधिनियम अवैध हो जाता है और इसलिये याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है और विवादित नोटिस को अवैध घोषित किया जा सकता है और उसे रद्द घोषित किया जा सकता है। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य को आरआईए का पक्ष होने के नाते याचिकाकर्ता पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ वह एक समझौते के माध्यम से कोई कर, उपकर लगाने या छूट नहीं देने पर सहमत नहीं हो सकता है या याचिकाकर्ता द्वारा देय रॉयल्टी और दूसरी ओर बाद में इस तरह के दिये गये अधिकार को विनियोजित करने वाला एक कानून बनाकर समझौते का सम्मान किये बिना आरआईए की शर्तों को रद्द कर दिया और इस तरह बिजली पैदा करने के लिये उपयोग किये जाने वाले पानी पर कर की मांग की है, जबकि यह 12 का आनन्द लेना जारी रख रहा है। पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) की शर्तों के तहत परियोजना से मुफ्त बिजली। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, राज्य का यह अधिनियम मनमाना है और लागू अधिनियम रद्द किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य के कृत्य याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः रिट याचिका प्रस्तुत की गयी है।

- 16.** प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है,

क्योंकि राज्य सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार बिजली उत्पादन के लिये पानी के भण्डारण और उपयोग पर कानून बनाने और चार्ज करने में सक्षम है। आगे यह कहा गया है कि अपने जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रतिबन्धित करने के लिये प्रतिवादी राज्य ने अपने सभी संसाधनों का मालिक होना आवश्यक समझा, जल संसाधनों का प्रबन्ध करे और इसका उचित प्रबन्धन करे ताकि भविष्य में जल संघर्ष से बचा जा सके। जल संसाधनों का प्रबन्ध करने, उन्हें अच्छी स्थिति में बनाये रखने, अध्ययन और अनुसंधान करने के लिये विचाराधीन अधिनियम बनाया गया था, जो राष्ट्रीय मसौदा जल नीति और कार्य योजना के अनुरूप है। विभिन्न देशों के उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां वर्तमान में जल उपयोग कर्ताओं विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं से जल शुल्क लिया जा रहा है, यह कहा गया है कि विस्तृत राज्य जल नीति तैयार करने के लिये पहले कदम के रूप में उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 सन् 2013) अस्तित्व में लाया गया। जिसके उद्देश्य से ही पता चलता है कि यह अधिनियम राज्य के भीतर जल संसाधनों को विनियमित करने के लिये उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण विधेयक की स्थापना का प्रावधान करने के लिये बनाया गया था। आगे कहा गया है कि चूंकि उत्तराखण्ड में प्रचुर जल संसाधन है, इसलिये बढ़ती मांग के कारण राज्य और राष्ट्र के लाभ के लिये इन स्रोतों को सर्वोत्तम संभव तरीके से संरक्षित और उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिये उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम 2012 अधिनियम के तहत परिभाषित जल स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिये पानी का उपयोग शुल्क वसूलने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये अस्तित्व में आया। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका बिल्कुल गलत आधारों पर है और भारतीय संविधान के स्थापित प्रावधानों के खिलाफ

है। बताया गया है कि प्रावधानों के अनुसार प्रविष्टि 17 भारत के संविधान की सूची II, जल, कहने का तात्पर्य यह है कि जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत परियोजनाएँ सूची II (राज्य सूची) में दी गई हैं सूची I (संघ) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन सूची I की प्रविष्टि 56 में विनियमन और शामिल है अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विकास इस तरह का विनियमन और किस हद तक संघ के नियंत्रण में विकास की घोषणा की जाती है संसद द्वारा कानून बनाकर जनता के समक्ष समीचीन बनाना हित और इस तरह के संसदीय विनियमन के तहत संविधान नेविगेशन तक ही सीमित है शिपिंग आदि लेकिन पानी के भंडारण और उपयोग के लिए नहीं बिजली का उत्पादन. एकमात्र कानून बनाया गया संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत है एकीकृत और को बढ़ावा देने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतरराज्यीय नदी घाटियों का इष्टतम विकास। यह कहा गया है कि अधिनियम में बोर्ड की परिकल्पना की गई है सिंचाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ निकाय, बाढ़ नियंत्रण नेविगेशन, जल संरक्षण। इन निकायों को सलाहकार निकाय होना चाहिए और उनके कार्य के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना है अंतरराज्यीय नदियों का विकास और विनियमन और नदी घाटी उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन प्रवेश के अंतर्गत है सूची-I के 56 में, केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है पानी के उपयोग पर शुल्क या टैरिफ पर कानून बनाएं प्राकृतिक उपभोक्ताओं से विद्युत उत्पादन जल संसाधन। सूची-I की प्रविष्टि 56 के अलावा, संघ संभवतः बाढ़ रोकने के लिए कदम उठाएगा, सूची-I की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत बांधों आदि का निर्माण जो अंतर्देशीय नौवहन और नेविगेशन की बात करता है संसद द्वारा जलमार्गों को राष्ट्रीय घोषित किया गया यांत्रिक चालित के संबंध में जलमार्ग जहाज. अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है चर्चा है कि राज्य सरकार बिल्कुल पानी के

उपयोग पर शुल्क पर कानून बनाने के लिए सक्षम प्राकृतिक जल से बिजली उत्पादन के लिए राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित संसाधन सरकार। काउंटर के पैरा-32 में शपथ पत्र में कहा गया है कि माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस पर सहमति दे दी है उक्त अधिनियम, 2012 का विधान राज्य द्वारा पारित किया गया विधायिका अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 163(2) ,इसलिए संविधान के अनुच्छेद 246 का उल्लंघन है नहीं उठता क्योंकि कानून बनाया गया मामला नहीं है वह मामला जो सूची I (संघ सूची) या में गिना गया है सूची II (समवर्ती सूची)।

17. प्रत्युत्तर शपथ पत्र में अधिकांश रिट याचिका में दिए गए कथनों को दोहराया गया है। यह कहा गया है कि सूची I की प्रविष्टि 56 विशेष रूप से भारत संघ को सभी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार देता है अंतरराज्यीय नदियों और इससे जुड़ी किसी भी नदी से संबंधित राज्य विधानमंडल को एक अतिरिक्त माना जाता है प्रादेशिक कानून और की शक्ति के उल्लंघन में संबंधित राज्य विधानमंडल. यह सार्वभौमिक है ज्ञात तथ्य कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी में डूबने तक न केवल उत्तराखंड से होकर बहती है बल्कि गुजरती भी है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के माध्यम से।

18. उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

19. जो मुद्दे विचार हेतु उठते हैं इस न्यायालय की रूपरेखा निम्नानुसार तैयार की गई है:

(i) क्या उत्तराखंड राज्य ने कर लगाने की विधायी क्षमता, या नहीं?

(ii) विवादित अधिनियम और कर नहीं लगाया जा सकता सातवीं की सूची II की प्रविष्टि 17 में रखा

गया है भारत के संविधान की अनुसूची यथावत है एक सामान्य प्रविष्टि और कर कायम नहीं रहेगा कानून; सूची II की प्रविष्टि 17 तक सीमित है 'कहने के लिए' शब्द और कर कानून का प्रतिपादन नहीं करता या एक कर.

(iii) सूची II की प्रविष्टि 17, प्रविष्टि 56 के अधीन है सूची I. अंतरराज्यीय विषय इसके अंतर्गत आता है संघ का विशिष्ट डोमेन. नदी गंगा एक अंतरराज्यीय नदी है, इसलिए है पूरी तरह से के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ और इसलिए राज्य अंतरराज्यीय नदी पर कर नहीं लगा सकते पानी।

(iv) चूंकि अधिनियम का शीर्षक "उत्तराखंड" है विद्युत उत्पादन अधिनियम पर जल कर, 2012" (अधिनियम) और धारा 12 आक्षेपित अधिनियम उत्पादन पर कर की बात करता है बिजली.

(v) क्या आक्षेपित अधिनियम जल अधिरोपित करता है कर पर संविधान के अनुच्छेद 288(2) का प्रभाव पड़ता है के राष्ट्रपति की सहमति न मिलने के कारण भारत?

(vi) क्या अधिसूचना धारा 151 के अंतर्गत है आक्षेपित अधिनियम की धारा 17(1) की दर तय करती है प्रति घन मीटर पानी के उपयोग के अनुसार कर बिजली का उत्पादन भी बराबर होता हैके अनुच्छेद 288(2) के तहत अनिवार्य रूप से अमान्य है संविधान?

(vii) क्या विवादित अधिनियम दुर्भावनापूर्ण है या राज्य की विधायिका का रंगारंग अभ्यास शक्तियां. आरआईए या अन्यथा द्वारा हस्ताक्षरित के शुरू होने से पहले याचिकाकर्ता यह अधिनियम अधिनियम के साथ विश्वासघात है?

(viii) क्या इसके विरुद्ध वचनबंधन है राज्य इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास है के रूप में कोई शुल्क या कर नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की आरआईए में निर्धारित? यदि राज्य के पास शक्ति होती बिजली उत्पादन पर कर लगाना, या नहीं?

(ix) प्रवाह मापने की स्थापना है मापने के लिए उपकरण नितांत आवश्यक है कराधान के प्रयोजनों के लिए जल प्रवाह?

20. आगे बढ़ने से पहले यह उचित होगा यहां निहित परिभाषाओं को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम का अध्याय I. वही निकाले जाते हैं यहाँ के अंतर्गत:

"परिभाषाएँ 2. इन नियमों में, जब तक कि न हो विषय या सन्दर्भ में कुछ भी प्रतिकूल :-

(ए) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखंड जल कर से है विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर;

(बी) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखंड राज्य से है बिजली पर जल कर के लिए आयोग धारा 21 के तहत स्थापित पीढ़ी अधिनियम का;

(सी) "बिजली" का अर्थ विद्युत ऊर्जा है किसी से खींचे गए पानी के माध्यम से उत्पन्न के क्षेत्र में बहने वाला जल स्रोत राज्य;

(डी) "सरकार" का अर्थ है सरकार उत्तराखंड;

(ई) "अधिसूचना" का अर्थ अधिसूचना है राज्य के राजपत्र में प्रकाशित, और शब्द "सूचित करें" का अर्थ लगाया जाएगा इसलिए;

(एफ) "उपयोगकर्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, समूह व्यक्ति, स्थानीय निकाय, सरकार विभाग, कंपनी, निगम, समाज आदि पानी खींचना या अन्य कोई के अध्याय-II के तहत अधिकृत प्राधिकरण पानी निकालने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिनियम की पीढ़ी के लिए किसी भी स्रोत से

बिजली;

(छ) "जल" का अर्थ निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन है किसी भी नदी, धारा, सहायक नदी, नहर में, नाला या कोई अन्य प्राकृतिक प्रवाह पानी या की सतह पर निर्धारित कोई भी भूमि जैसे, तालाब, लैगून, दलदल, वसंत;

(ज) "जल स्रोत" का अर्थ है एक नदी और उसका सहायक नदियाँ, धारा, नाला, नहर, झरना, तालाब, झील, जलधारा या कोई अन्य वह स्रोत जहाँ से पानी खींचा जाता है बिजली पैदा करता है

(आई) "जल कर" का अर्थ है लगाई गई दर या के उत्पादन के लिए निकाले गए पानी के लिए शुल्क लिया गया बिजली और इस अधिनियम के तहत तय।"

21. सबसे पहले, श्री गौरव बनर्जी, श्री वीके कोहली, श्री मोहन परासरन, श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता श्री डीएस पाटनी याचिकाकर्ताओं और श्री की ओर से उपस्थित हुए। -आदित्य सिंह, रिट बैच में विद्वान वकील याचिकाएँ यह प्रस्तुत करेंगी कि यदि आक्षेपित अधिनियम तो, सूची II की किसी भी प्रविष्टि में नहीं आता है यह संविधान और उससे परे भी अधिकारातीत है राज्य की विधायी क्षमता. उन्होंने चित्र बनाया इस न्यायालय का ध्यान सूची की प्रविष्टि 17 की ओर है II, जो इस प्रकार है:

"17. जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, पानी भंडारण और जल विद्युत के प्रावधानों के अधीन सूची I की प्रविष्टि 56।"

22. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रवेश शुल्क लगाने की शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता आक्षेपित कर और कोई वैधता प्रदान नहीं करता है ऐसा लगाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता कर। उक्त प्रविष्टि से संबंधित एक 'सामान्य प्रविष्टि' है विषय वस्तु 'जल और संबद्ध मामले' और है 'कर प्रविष्टि'

नहीं है और कोई भी प्रदान नहीं करता है राज्य को गैर-कर लगाने का अधिकार पानी का अत्यधिक उपभोग.

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केसोराम इंडस्ट्रीज लि. केस 8. उक्त निर्णय का पैरा 31, उप पैरा 3 है यहां से निकाला गया:

"31(3) कराधान को एक अलग माना जाता है विधायी सक्षमता के प्रयोजनों के लिए मामला। वहाँ है के सामान्य विषयों के बीच किया गया भेद विधान और कराधान. के सामान्य विषय विधान को प्रविष्टियों के एक समूह में निपटाया जाता है एक अलग समूह में कराधान की शक्ति. करने की शक्ति सामान्य विधायी प्रविष्टि से कर की कटौती नहीं की जा सकती एक सहायक शक्ति के रूप में।"

24. पर और भी भरोसा किया गया है पैराग्राफ नं. 74(3) केसोराम के मामले में, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

"74(3) कराधान को शामिल करने का इरादा नहीं है मुख्य विषय में जिसमें यह विस्तारित हो सकता है निर्माण को शामिल माना जाएगा, लेकिन माना जाएगा विधायी प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला योग्यता. और यह भेद प्रकट भी होता है अनुच्छेद 248 खंड (1) और (2) और की भाषा संविधान की सूची I में प्रविष्टि 97। नीचे सूचियों में प्रविष्टियों की योजना, कराधान पर विचार किया जाता है एक विशिष्ट मामले के रूप में और अलग से निर्धारित किया गया है।"

25. पैराग्राफ नं. 75, 76 और 100 की केसोराम के मामले पर भी भरोसा किया जाता है. वही पढ़ा निम्नानुसार:

"75. एमपीवी सुंदररामियर एंड कंपनी का जिक्र करते हुए। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1958

एससी 468, सब्यसाची मुखर्जी, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) छह के लिए बोल रहे थे पीठ का गठन करने वाले सात न्यायाधीशों में से सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 17 ने इसे इसके अंतर्गत रखा में शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक योजना सातवीं अनुसूची से संबंधित अलग-अलग प्रविष्टियाँ हैं कराधान और अन्य कानूनों के लिए। कर नहीं लगाया जा सकता एक सामान्य प्रविष्टि के अंतर्गत.

76. उपरोक्त सिद्धांत कायम हैं क्षेत्र और मामलों के बाद मामलों में इसका पालन किया गया है।

100. अनुच्छेद 265 आदेश - कोई कर नहीं लगेगा कानून के अधिकार के अलावा लगाया या एकत्र किया गया। सातवीं अनुसूची की योजना एक विस्तृत खुलासा करती है विधायी विषयों की गणना, काफी हद तक पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम से अधिक विस्तारित। सूची I में प्रविष्टि 97 अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है संसद। संविधान का अनुच्छेद 248 जो विधान प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है कोई भी कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति समवर्ती में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में सूची या राज्य सूची. साथ ही, यह वह भी प्रदान करता है ऐसी अवशिष्ट शक्ति में बनाने की शक्ति शामिल होगी कर लगाने वाले किसी भी कानून का इनमें से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया है सूचियाँ। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई कर लगाने की शक्ति स्पष्ट रूप से है सूची II में उल्लेखित है, तो वह उपलब्ध नहीं होगा की धारणा के आधार पर संसद द्वारा प्रयोग किया जाएगा अवशिष्ट शक्ति. यूनियन में सात जजों की बेंच भारत बनाम हरभजन सिंह दिल्ली, (1971) 2 एससीसी 779 4:3 के बहुमत से कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई किसी मामले का सम्मान अपने साथ कोई शक्ति नहीं रखता हमारी संवैधानिक योजना के तहत

कर लगाओ...."

26^ण केसोराम के न्याय के बल पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय के पैरा 76 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से माना है उपर्युक्त सिद्धांत क्षेत्र को कायम रखता है और प्रत्येक मामले में इसका पालन किया गया है। यह है स्पष्ट रूप से माना गया है कि कर नहीं लगाया जा सकता है एक सामान्य प्रविष्टि के अंतर्गत. की वैधता के संबंध में अधिनियम, बहुत कम, सूची II की प्रविष्टियाँ 17 और 18 तर्क दिया गया है कि दोनों प्रविष्टियाँ सामान्य हैं के तहत प्रविष्टियाँ और कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है आधिकारिक की दृष्टि से सामान्य प्रविष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा केसोराम का फैसला।

27. विद्वान वरिष्ठ का अगला तर्क याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील हैं राज्य का मामला मुख्यतः इसी पर निर्भर है सातवीं की सूची II की प्रविष्टियाँ 49, 45 और 48 संविधान की अनुसूची. वैसा ही पढ़ा जाता है अंतर्गत:

"45. भू-राजस्व, मूल्यांकन सहित और राजस्व का संग्रह, भूमि का रखरखाव अभिलेख, राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण और अभिलेख अधिकार और राजस्व का हस्तांतरण।

48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क.

49. भूमि और भवनों पर कर।"

28. यह तर्क दिया गया है कि राज्य के अनुसार, प्रविष्टियाँ 48 और 49 "भूमि" से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे सब कुछ शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और अभिव्यक्ति "भूमि" को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें संग्रहीत पानी भी शामिल है ज़मीन पर या ज़मीन पर बहते हुए।"

29. केसोराम के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उक्त फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूची II की प्रविष्टि 49 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'भूमि' के दायरे

और दायरे पर विचार किया है। पैराग्राफ नं. उक्त निर्णय का 44 यहां दिया गया है:

सूची I में प्रविष्टि 86 एकत्रीकरण के सिद्धांतों पर आगे बढ़ती है और सभी संपत्तियों के मूल्य की समग्रता पर कर लगाया जाता है। सूची II में प्रविष्टि 49 के तहत कराधान के उद्देश्य से भूमि और भवनों को अलग करना काफी स्वीकार्य है। सूची II में प्रविष्टि 49 में प्रयुक्त भाषा के आयाम को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। शहरी भूमि के बाजार मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की दर से गणना की गई कर की वसूली को राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अंतर्गत माना गया था और सूची I में प्रविष्टि 86 पर लागू नहीं किया गया था। श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका मामले में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा,

30. सहायक के बल पर. शहरी भूमि कर आयुक्त के निर्णय, जैसा कि केसोराम के मामले में दोहराया गया है, में कहा गया है कि विवादित कर सीधे भूमि पर नहीं लगाया जाता है (उदाहरण के लिए, संपत्ति कर/नगरपालिका कर) और इसका भूमि से कोई निश्चित संबंध नहीं है, अर्थात्, इसका जमीन से कोई सांठगांठ नहीं. इसलिए, लगाए गए कर को किसी भी तरह से सूची II की प्रविष्टि 49 में नहीं जोड़ा जा सकता है।

31. यह तर्क दिया गया है कि सूची II की प्रविष्टि 48 भी वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक है और बिल्कुल भी शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त प्रविष्टि कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क से संबंधित है।

32. सूची II की प्रविष्टि 45 के संबंध में बहस करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड 16 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि 'भूमि राजस्व' शब्द को संविधान पीठ द्वारा न्यायशास्त्रीय रूप से समझाया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 20 और 21 निम्नानुसार हैं:

"20.प्रविष्टि 45 भूमि राजस्व से संबंधित है, जो एक प्रसिद्ध अवधारणा है और संविधान लागू होने से पहले भारत में अस्तित्व में है। एनआर रेड्डी, जगनमोहन

रेड्डी, जे. विद्वान न्यायाधीश के रूप में तब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि मद्रास के समग्र राज्य में कोई भूमि राजस्व अधिनियम मौजूद नहीं था और न ही विधायी अधिनियम द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली कभी स्थापित की गई थी। रिपोर्ट के पृष्ठ 306 पर विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि पहले के दिनों में, संप्रभु अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सभी खेती योग्य भूमि की उपज का एक हिस्सा दावा करते थे, जिसे 'राजभागम' या विभिन्न अन्य नामों से जाना जाता था, और थे समय-समय पर उनकी इच्छा और खुशी के अनुसार उनका हिस्सा या उसका परिवर्तित धन मूल्य तय किया जाता है..."

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि सदियों की अवधि में, भारत में भू-राजस्व ने भूमि की उपज में हिस्सेदारी का एक सांकेतिक अर्थ प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने का हकदार राजा या सरकार है।"

33. इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के फैसले के आधार पर, विद्वान वरिष्ठ वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि भू-राजस्व को कर सरलता के बराबर नहीं किया जा सकता है और इसे भूमि से उपज पर संप्रभु के हिस्से के साथ सहसंबंधित किया जाना चाहिए जैसा कि परंपरागत रूप से समझा जाता है और इसमें है भूमि के उपयोग के लिए रॉयल्टी की प्रकृति जिसके परिणामस्वरूप भूमि से प्राप्त लाभ की खपत होती है। वे आगे कहेंगे कि वर्तमान मामले में पानी की बिल्कुल भी खपत नहीं है। पानी का उपयोग केवल जनरेटरों में डालने के उद्देश्य से किया जाता है, जो बिजली का उत्पादन करते हैं और उसके बाद इसे किसी भी तरीके से उपयोग किए बिना नीचे की ओर प्रवाहित कर दिया जाता है। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि पानी की खपत के अभाव में, पानी के उपयोग पर कोई कर या उपकर नहीं लगाया जा सकता है।

34. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी ने अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया कि 'भूमि' शब्द

बहुत व्यापक है और इसमें सतह के ऊपर या नीचे की सभी चीजें शामिल हैं:

- (i) रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड रामपुर बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, रामपुर, AIR 1962 इलाहाबाद
- (ii) निज़ाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बनाम सिटी नगर पालिका, एआईआर 1965 एपी 91
- (iii) आरएस रेखचंद मोहोटा स्पनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 6 एससीसी
- (iv) इच्छापुर औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य, (1997) 2 एससीसी 42
- (v) इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (1990) 1 एससीसी 12
- (vi) बिहार राज्य और अन्य बनाम भारतीय एल्युमीनियम कंपनी और अन्य, (1997) 8 एससीसी 360

35. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 में पाई जाने वाली विधायिका की क्षमता के संबंध में है, विधायी क्षमता के किसी भी कानून का निर्णय केवल दो आधारों पर किया जाना है और किसी पर नहीं अन्यथा। पहला आधार यह है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत उस कानून को बनाना राज्य की विधायी क्षमता में होना चाहिए। दूसरा आधार यह है कि यह केवल विधायी सक्षमता या मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन होना चाहिए। तीसरा आधार संविधान द्वारा अनुच्छेद 288 और 304 ए और 192 के तहत व्यक्त की गई सीमा है। अनुच्छेद 245 भारत का संविधान संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि जब तक अनुचितता न हो विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य 12 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संसद या उस मामले के लिए, राज्य

विधानमंडल की शक्ति दो तरह से प्रतिबंधित है। संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अदालतें केवल दो आधारों पर रद्द कर सकती हैं, अर्थात्, (1) विधायी क्षमता की कमी और (2) संविधान के भाग III में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन। या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का. कोई तीसरा आधार नहीं है.

36. यह आधार कि लगाया गया कर बिजली उत्पादन पर है, बिल्कुल गलत है। यहां कर "पानी खींचने" की गतिविधि पर लगाया जा रहा है और कर की वास्तविक प्रकृति यह है कि यह "पानी खींचने या उसके उपयोग" पर है। यह है उपयोग किए गए पानी की मात्रा पर मूल्यांकन किया गया न कि उत्पादित बिजली की इकाइयों पर। जहां तक प्रविष्टि 54 और 56 का संबंध है, दोनों प्रविष्टियां सामान्य नियामक प्रविष्टियां हैं जिन पर कर नहीं लगता है। वे "पानी के उपयोग" पर कर लगाने की राज्य की शक्ति को भी प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं जो सूची II, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये दोनों प्रविष्टियाँ गैर-कर प्रविष्टियाँ होने के कारण कराधान से संबंधित नहीं हैं। जहां तक प्रविष्टि 97 का सवाल है, विवादित कर कानून सीधे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17, 18, 45, 49, 50 में पाया जा सकता है और प्रविष्टि 97 की यहां कोई भूमिका नहीं है। इसी प्रकार, सूची III की प्रविष्टि 38, एक गैर-कर प्रविष्टि होने या एक सामान्य नियामक प्रविष्टि होने के नाते, कर लगाने या "अपने स्रोत से पानी के उपयोग" पर कर लगाने की राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए शायद ही प्रासंगिक है। इसके तहत कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता. इस मामले में जल कर लगाने की कर लगाने की शक्ति का अनुमान प्रविष्टि 17, 18, 45, 49 और 50 से लगाया जा सकता है। यदि इन्हें सामूहिक रूप से पढ़ा जाए तो राज्यों के पास बिजली पैदा करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा पानी के उपयोग पर कर लगाने की पर्याप्त शक्ति है। इस प्रकार, उत्तराखंड राज्य के पास कर लगाने की विधायी क्षमता है।

37. याचिकाकर्ता एएचपीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम के

शीर्षक - "बिजली उत्पादन पर जल कर" की ओर आकर्षित किया। उनका कहना था कि उक्त अधिनियम पानी पर कर लगाने का प्रावधान करता है जब पानी बिजली उत्पादन के लिए निकाला जाता है, न कि जब पानी किसी अन्य उद्देश्य के लिए खींचा जाता है। दूसरे शब्दों में, विवादित अधिनियम के तहत कर केवल तभी लगाया जा सकता है जब पानी की निकासी से बिजली का उत्पादन होता है। यह तर्क दिया गया है कि विवादित अधिनियम बिजली उत्पादन पर कर लगाता है जिसे विवादित अधिनियम के तहत केवल जल कर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, विवादित अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित अधिनियम, सार और सार में "बिजली उत्पादन" के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी पर एक कर है और "पर कर नहीं है।" पानी"। यह तर्क दिया गया है कि बिजली उत्पादन पर कर सूची I की प्रविष्टियों 54, 56, 84 और 97 पर आता है और इसलिए, राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत कर लगाने में अक्षम है। यह तर्क दिया जाता है कि सूची II की प्रविष्टि 17 किसी राज्य को पानी के उपयोग पर ऐसा कोई कर लगाने के लिए अधिकृत या सशक्त नहीं बनाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एआईआर 1962 सभी 83 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसे नगर परिषद कोटा 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, और उक्त फैसले के आधार पर वह प्रस्तुत करेंगे कि कर का नामकरण प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो प्रासंगिक है वह कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है। बल्कि, वर्तमान अधिभार सीधे भूमि पर कर नहीं है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज, (2004) 10 एससीसी 201 में अपने फैसले में संविधान पीठ द्वारा समझाया गया था। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि कर भूमि पर नहीं बल्कि कथित तौर पर लगाया जा रहा है। पानी पर, उक्त निर्णय के अनुपात का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि कर पानी पर है, सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत यह भूमि पर कर नहीं है। नगर परिषद कोटा 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, और उक्त निर्णय के आधार पर वह प्रस्तुत करेंगे कि कर का नामकरण प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो

प्रासंगिक है वह कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है। बल्कि, वर्तमान अधिभार सीधे भूमि पर कर नहीं है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज, (2004) 10 एससीसी 201 में अपने फैसले में संविधान पीठ द्वारा समझाया गया था। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि कर भूमि पर नहीं बल्कि कथित तौर पर लगाया जा रहा है। पानी पर, उक्त निर्णय के अनुपात का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि कर पानी पर है, सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत यह भूमि पर कर नहीं है। नगर परिषद कोटा⁹ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, और उक्त निर्णय के आधार पर वह प्रस्तुत करेंगे कि कर का नामकरण प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो प्रासंगिक है वह कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है। बल्कि, वर्तमान अधिभार सीधे भूमि पर कर नहीं है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज, (2004) 10 एससीसी 201 में अपने फैसले में संविधान पीठ द्वारा समझाया गया था। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि कर भूमि पर नहीं बल्कि कथित तौर पर लगाया जा रहा है। पानी पर, उक्त निर्णय के अनुपात का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि कर पानी पर है, सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत यह भूमि पर कर नहीं है। लेकिन जो प्रासंगिक है वह कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है। बल्कि, वर्तमान अधिभार सीधे भूमि पर कर नहीं है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज, (2004) 10 एससीसी 201 में अपने फैसले में संविधान पीठ द्वारा समझाया गया था। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि कर भूमि पर नहीं बल्कि कथित तौर पर

लगाया जा रहा है। पानी पर, उक्त निर्णय के अनुपात का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि कर पानी पर है, सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत यह भूमि पर कर नहीं है।

यह तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है जो सामान्य प्रविष्टि के बावजूद पानी के उपयोग के लिए "पानी" पर कर लगाने का राज्य को स्पष्ट रूप से अधिकार देती है, राज्य "भूमि" और "खनिज" के कराधान के लिए अन्य प्रविष्टियों की व्यापक व्याख्या करके इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। "और विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत इन शर्तों को दी गई परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालकर, पानी के उपयोग पर जल कर को उनकी विधायी क्षमता में लाना।

38. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी यह प्रस्तुत करेंगे कि विवादित अधिनियम के तहत कर की घटना 'पानी की निकासी' है और बिजली का उत्पादन एक अलग और बाद की गतिविधि है जिसमें कुछ भी नहीं है आक्षेपित अधिनियम से संबंधित. यह तर्क दिया गया है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, इसका सार और सार, कर योग्य घटना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर ही देखा जा सकता है। धारा 2(एफ), (जी) और (आई) धारा 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18 के साथ पढ़ें। 19 और 25(5) स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कर "बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी/उपयोगकर्ता" के संबंध में है। धारा 3(2), 4, 5, 10, 12, 14, 18 और 19 में "उपयोगकर्ता द्वारा खींचा गया पानी" और "बिजली का उत्पादन" वाक्यांश के बीच प्रयुक्त शब्द "के लिए" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लेवी गतिविधि पर है अपने उपयोगकर्ता के लिए पानी खींचने का। "बिजली उत्पादन के लिए" केवल यह दर्शाता है कि पानी के केवल ऐसे उपयोगकर्ता पर कर लगाया जाएगा जो बिजली उत्पादन के लिए है, लेकिन कर निकाले गए या उपयोग किए गए पानी पर है। क्षण पानी निकाला जाता है तो टैक्स लगाया जाता है. यह मुख्य रूप से धारा 2(एच) के तहत किसी भी जल स्रोत से पानी खींचने के लिए उपयोगकर्ता पर लगने वाला कर है। कर का विषय "पानी

का उपयोगकर्ता" है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है लेकिन कर का भार केवल पानी खींचने पर पड़ता है, बिजली उत्पादन पर नहीं। यह तर्क दिया गया है कि यदि कर बिजली उत्पादन पर था तो कर का उचित माप "उत्पादित बिजली की इकाइयों" पर होगा, न कि "पैसे प्रति घन मीटर निकाले गए पानी" पर। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि कर "बिजली उत्पादन" पर है, पूरी तरह से गलत है। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं ने जिन प्रविष्टियों पर भरोसा किया है, यानी, सूची I की प्रविष्टियाँ 54, 56, 84 और 97, यह दिखाने के लिए कि बिजली उत्पादन पर कर सूची I की इन प्रविष्टियों पर पड़ता है और इसलिए, राज्य के पास कोई विधायी नहीं है। योग्यता पूर्णतया निराधार है।

39. यह सच है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, उसका सार और सार, कर योग्य घटना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर ही देखा जा सकता है। लेवी की प्रकृति और चरित्र का पता लगाते समय मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। न्यायालय को मामले के सार को देखना होगा। मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत कभी-कभी कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधानमंडल द्वारा विधान को दिया गया नाम महत्वहीन है। संपूर्ण अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए।

40. याचिकाकर्ता मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आदित्य सिंह ने कहा कि खनिज होने के कारण पानी अब खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एक नियामक प्रविष्टि, प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित है। इस प्रकार, राज्य के पास अधिनियम के तहत खनिजों पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

41. इस न्यायालय की राय में, चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 एक नियामक प्रविष्टि है और कर लगाने वाली प्रविष्टि नहीं है, इसलिए, उक्त

प्रविष्टि "भूमि या खनिज" पर कर लगाने की राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। " सूची II की प्रविष्टियाँ 49 और 50 के अंतर्गत।

42. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि प्रविष्टियाँ 48 और 49 'भूमि' से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे की हर चीज़ शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और अभिव्यक्ति 'भूमि' का व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए, भूमि पर संग्रहीत या भूमि पर बहने वाले पानी को शामिल करना। इच्छापुर इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पानी खनिज की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए, राज्य प्रविष्टि 49 से पानी पर कर लगाने के लिए विधायी क्षमता प्राप्त कर सकता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II।

43. इच्छापुर इंडस्ट्रीज के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं:

"17. अधिनियम में संशोधन के बाद "खनिज" के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के अधिकार की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी कानूनी तौर पर "पानी" लाने और ले जाने के लिए संबंधित भूमि के माध्यम से पाइपलाइन बिछा सकते हैं, बशर्ते "पानी" "एक "खनिज" है।

18. "खनिज" की परिभाषा जो हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, यह इंगित करेगी कि खान अधिनियम, 1952 में इसका दिया गया अर्थ संदर्भ या निगमन द्वारा विधान के क्लासिक सिद्धांत के आधार पर यहां भी लागू किया जाना है जो एक विधायी उपकरण है पहले के अधिनियम के प्रावधानों को बाद के अधिनियम में शब्दशः पुनरुत्पादित करने से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से अपनाया गया। इस प्रकार शामिल किए गए प्रावधान बाद के अधिनियम का हिस्सा और पार्सल बन गए जैसे कि उन्हें इसमें भौतिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया

हो।

19. इस सिद्धांत पर खान अधिनियम, 1952 में निर्धारित "खनिज" की परिभाषा को भौतिक रूप से हटा दिया गया है और इस अधिनियम में शामिल माना जाएगा। इसलिए, हमें "खनिज" शब्द का सही अर्थ जानने के लिए उस अधिनियम को देखना होगा जिसे धारा 2 (जेजे) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. (जेजे) 'खनिज' का अर्थ है वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी से खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, उत्खनन या किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें खनिज तेल (जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं) शामिल हैं।"

20. परिभाषा से संकेत मिलता है कि "खनिज" वे पदार्थ हैं जिन्हें परिभाषा में इंगित विभिन्न तकनीकी उपकरणों, अर्थात् "खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, उत्खनन" का उपयोग करके पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है। इन शब्दों के बाद "किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा" शब्द आते हैं। इन शब्दों के पिछले शब्दों, अर्थात् खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, आदि के साथ निकटता के कारण, उन्हें उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए और इसलिए, यदि "खनिज" किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं "ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए खनन, खुदाई, ड्रिलिंग आदि में शामिल उपकरण या ऑपरेशन के समान एक ऑपरेशन हो। परिभाषा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता "पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त किए जा सकते हैं" शब्दों का उपयोग है। जो इंगित करते हैं कि "खनिजों" को आवश्यक रूप से पृथ्वी में समाहित होने या पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे या तो पृथ्वी की सतह पर या नीचे उपलब्ध हो सकते हैं। यदि सतह पर "खनिज" उपलब्ध है, तो जो ऑपरेशन स्पष्ट रूप से नियोजित किया जाएगा वह ड्रेजिंग, उत्खनन या हाइड्रोलिकिंग या कोई अन्य

समान ऑपरेशन होगा। इसलिए, परिभाषा बहुत व्यापक है लेकिन इसके व्यापक अर्थ के बावजूद पृथ्वी से प्राप्त होने वाला प्रत्येक पदार्थ "खनिज" नहीं होगा।

23. लेकिन ऐसे भूमिगत जल भी हैं जो पूरी तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित हैं और जो या तो सतह के स्तर से रिसते हैं या रिसते हैं, बिना किसी निर्धारित चैनल (रिसते पानी) के माध्यम से या एक स्थायी और नियमित लेकिन अदृश्य मार्ग में बहते हैं, या झूठ बोलते हैं। पृथ्वी के नीचे एक कमोबेश अचल शरीर में, एक भूमिगत झील के रूप में। यह पानी केवल "ड्रिलिंग" की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें चैंबर्स डिक्शनरी के अनुसार "बोरिंग" भी शामिल है।

24. अब, यदि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे ड्रिलिंग की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है। यह तुरंत इस अधिनियम में निर्धारित और रखी गई "खनिज" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अन्यथा भी, एचएच रीड, एफआरएस, इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लंदन विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस द्वारा प्रकाशित रटले के एलिमेंट्स ऑफ मिनरलॉजी, 26वें संस्करण में "मिनरल" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना और परमाणु संरचना वाला पदार्थ है और प्रकृति की अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है।"

25. इस परिभाषा के आधार पर रटले कहते हैं:-

"फिर से, पानी, बर्फ और बर्फ परिभाषा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे एक निश्चित रासायनिक संरचना के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सजातीय अकार्बनिक पदार्थ हैं।

27. सिविल अपील क्र. 1983 का 10538, हमारे द्वारा 17.12.1996 को तय किया गया, हमने पहले ही "परिभाषा" की व्याख्या करने के लिए नियम का संकेत दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि परिभाषा को

उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया था बनाया। हमने देखा कि जहां परिभाषा खंड के पहले शब्द "जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो" आता है, परिभाषा की व्याख्या उस संदर्भ के आलोक में की जानी चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है। हमने अवलोकन किया:

"इसका तात्पर्य यह है कि किसी कानून में किसी भी अन्य शब्द की तरह, एक परिभाषा को अधिनियम के संदर्भ और योजना के साथ-साथ उस उद्देश्य के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए जिसके लिए अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया गया था।"

28. यदि इस पृष्ठभूमि में प्रश्न की जांच की जाती है, तो यह देखा जाएगा कि "खनिज" की परिभाषा को खान अधिनियम, 1952 से हटा दिया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों (उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) में रखा गया है। भूमि अधिनियम, 1962 को जानबूझकर संशोधन अधिनियम संख्या द्वारा पेश किया गया था। 1977 का 13 ताकि पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम ले जाने के दौरान, किसी अन्य खनिज को भी इसके माध्यम से ले जाया जा सके। इसलिए, यदि पानी को "खनिज" के रूप में माना जाता है तो ओएनजीसी के लिए इसे धारा 3 के तहत बिना किसी अधिसूचना या घोषणा के किसी अन्य पाइपलाइन के माध्यम से ले जाने की अनुमति होगी। या अधिनियम के 6. यह व्याख्या जो "खनिज" की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुरूप है, पेट्रोलियम विज्ञापन खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के उद्देश्य को पूरा करती है। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि "पानी" इसे उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जिस अर्थ में आम आदमी समझता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।" यह कार्यसंसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य विशेष

प्रौद्योगिकी और उसमें शामिल वस्तुओं से निपटना है। इसलिए, हमारा विचार है कि इस अधिनियम में, "पानी" का उपयोग दोनों अर्थों में किया गया है, अर्थात्, (i) यह एक खनिज है; और (ii) पृथ्वी पर सबसे आम, आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पदार्थ।"

44. यह न्यायालय प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क से पूरी तरह सहमत है। प्रविष्टियाँ 48 और 49 'भूमि' से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे की हर चीज़ शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और 'भूमि' शब्द का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए, जिसमें भूमि पर संग्रहीत या भूमि पर बहने वाले पानी को शामिल किया जाना चाहिए। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के मद्देनजर यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि चूंकि "पानी" खनिज की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए, राज्य सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 से पानी पर कर लगाने की विधायी क्षमता प्राप्त कर सकता है। भारत का संविधान.
45. याचिकाकर्ता टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मोहन परासरन ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला:
46. अधिनियम की धारा 2(i), "जल कर" को "इस अधिनियम के तहत बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी के लिए लगाई या चार्ज की गई दर" के रूप में परिभाषित करती है।
47. धारा 2(एफ) 'उपयोगकर्ता' शब्द को किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, कंपनी, निगम, समाज आदि के रूप में परिभाषित करती है जो पानी खींचती है या अधिनियम के अध्याय II के तहत लाभ उठाने के लिए अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी है। बिजली उत्पादन के लिए किसी भी स्रोत से पानी खींचने की सुविधा।
48. धारा 10 के बारे में बताया गया है - बिजली उत्पादन के लिए पानी (गैर-उपभोग्य उपयोग) का उपयोग करने का हकदार उपयोगकर्ता को अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता और आयोग

के बीच एक समझौते के निष्पादन के बाद एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा

49. अधिनियम की धारा 12(1) चार्जिंग धारा है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"(1) पंजीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी के लिए जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

50. अधिनियम की धारा 17(i) कहती है - उपयोगकर्ता अधिनियम के तहत ऐसी दरों पर जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है।

51. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराशरन का कहना था कि अधिनियम के तहत लेवी बिजली उत्पादन के उद्देश्य से पानी के गैर-उपभोग्य उपयोग पर है और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा जाना चाहिए सूची II की प्रविष्टि 45 और 49 के तहत राज्य की विधायी क्षमता तय करते समय ध्यान में रखें। उनके अनुसार, सूची II की प्रविष्टि 45 भूमि राजस्व से संबंधित है और प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों पर कर से संबंधित है और दोनों का उपयोग राज्य द्वारा पानी के गैर-उपभोग्य उपयोग पर कर लगाने की वैधता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।

52. अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में श्री परासरन द्वारा दिया गया अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता टीएचडीसी 2006 और 2011 से टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के संबंध में गंगा और भागीरथी नदियों से पानी ले रहा है। परियोजना, क्रमशः, बिजली उत्पादन और एक साथ अंतर-राज्यीय बिक्री और खपत के लिए। कहा गया है कि गंगा नदी एक अंतरराज्यीय नदी है और भागीरथी नदी भी इसकी सहायक नदी है गंगा नदी. विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में शामिल किसी भी प्रविष्टि में किसी भी मामले पर विचार या उल्लेख नहीं किया गया है, जो पानी के उपयोग या खपत,

उपभोग्य या अन्यथा पर कर लगाने से संबंधित है। सूची II में निहित एकमात्र प्रविष्टि, प्रविष्टि 17 है जो राज्य विधायिका को जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों के जल निकासी और जल भंडारण के साथ-साथ जल शक्ति के संबंध में कानून बनाने और बनाने पर विचार करती है, लेकिन यह लागू करने के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं करती है। पानी पर कर. उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि विधायी शक्ति में सभी आकस्मिक और सहायक शक्ति शामिल हैं, कर लगाने की शक्ति हमारे संविधान के तहत ऐसी शक्ति नहीं है। प्रत्येक संघ और राज्य सूची, जो सूची I और II हैं, पहले कराधान शक्तियों से अलग सामान्य विधायी शक्तियां प्रदान करने वाली प्रविष्टियों की गणना करके शुरू होती हैं। सूची I के आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है सूची I के आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है सूची I के आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से

अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है और यह सूची I की प्रविष्टि 97 के आधार पर केंद्र सरकार की शक्ति होगी। दूसरे शब्दों में, कर लगाने की राज्य की शक्ति को किसी भी सामान्य प्रविष्टि (सूची II की प्रविष्टि 1 से प्रविष्टि 44 तक) में नहीं खोजा जा सकता है और किया जा सकता है केवल तभी लगाया जाता है जब यह किसी कर संबंधी प्रविष्टियों (सूची II की प्रविष्टि 45 से 63) तक पता लगाने योग्य हो। इसलिए, सूची II में किसी विशिष्ट कर प्रविष्टि के अभाव में, राज्य के पास अधिनियम के माध्यम से कर लगाने की कोई शक्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है।

53. उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया है:

"68. श्री वेणुगोपाल ने इस संबंध में आग्रह किया है कि यह संघ सूची की प्रविष्टि 97 है जो एक अंतरराज्यीय नदी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के विषय से संबंधित है। के जल का उपयोग, वितरण और नियंत्रण ऐसी नदियाँ अपने आप में कोई ऐसा विषय नहीं है जो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। उनके अनुसार, यह प्रविष्टि 56 में शामिल विषय नहीं है, जो केवल अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास की बात करता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण नदियों और नदी घाटियों, न कि किसी विशेष स्थान पर पानी। . (जोर दिया गया) इसके अलावा, उनके अनुसार, विनियमन और विकास का विभिन्न तटवर्ती राज्यों के बीच अंतर-राज्य नदी के पानी के उपयोग, वितरण या आवंटन से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, उस विषय को उक्त अवशिष्ट प्रविष्टि 97 द्वारा कवर किया गया माना जाना चाहिए।

विद्वान वकील के संबंध में, प्रविष्टि 97 की इस व्याख्या को स्वीकार करना संभव नहीं है। ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि, हमारे अनुसार, प्रविष्टि 56 में "अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास" की अभिव्यक्ति होगी। इसमें विभिन्न तटीय राज्यों के बीच अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के पानी का उपयोग, वितरण और आवंटन शामिल है। अन्यथा संघ को अपने नियंत्रण में विनियमन और विकास का अधिकार प्रदान करने की संविधान सभा की मंशा का कोई मतलब नहीं है और उद्देश्य पूरा करता है। आगे क्या है, नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 जो अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए प्रविष्टि 56 के तहत अधिनियमित किया गया है, अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण और आवंटन के क्षेत्र को कवर करता है।

इससे पता चलता है कि प्रविष्टि 56 में अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के "विनियमन और विकास"

की अभिव्यक्ति को विधायी रूप से तटवर्ती राज्यों के बीच अंतर-राज्य नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या आवंटन को भी शामिल किया गया है। .हमारा यह भी विचार है कि किसी राज्य की सीमाओं के भीतर एक अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के जल में प्रविष्टि 17 के संचालन को नियंत्रित करना और राज्य विधायिका को हस्तक्षेप करने या प्रभावित करने या विस्तार करने की क्षमता से वंचित करना है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने क्षेत्र से परे ऐसी नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और आवंटन के लिए, शेष प्रविष्टि 97 पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रविष्टि 56 के तहत उचित घोषणा पर्याप्त होगी। हमारे जैसे संघीय संविधान का आधार ही ऐसी व्याख्या का आदेश देता है और इसके विपरीत कोई व्याख्या नहीं की जाएगी जो संवैधानिक योजना और संविधान को ही नष्ट कर देगी। हालाँकि, इसलिए, अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के "विनियमन और विकास" को उसके पानी के "उपयोग, वितरण और आवंटन" से अलग करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन ऐसा करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है। हमारे जैसे संघीय संविधान का आधार ही ऐसी व्याख्या का आदेश देता है और इसके विपरीत कोई व्याख्या नहीं की जाएगी जो संवैधानिक योजना और संविधान को ही नष्ट कर देगी। हालाँकि, इसलिए, अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के "विनियमन और विकास" को उसके पानी के "उपयोग, वितरण और आवंटन" से अलग करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन ऐसा करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है। हमारे जैसे संघीय संविधान का आधार ही ऐसी व्याख्या का आदेश देता है और इसके विपरीत कोई व्याख्या नहीं की जाएगी जो संवैधानिक योजना और संविधान को ही नष्ट कर देगी। हालाँकि, इसलिए, अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के "विनियमन और विकास" को उसके पानी के "उपयोग, वितरण और आवंटन" से अलग करना

तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन ऐसा करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है।

70. अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों और उनके जल से संबंधित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि अधिनियम, अर्थात्, अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया जा सकता है और केवल अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया है। संविधान के 262 .इसे प्रविष्टि 56 के तहत अधिनियमित नहीं किया गया है क्योंकि यह विवादों के फैसले से संबंधित है और समग्र रूप से अंतर-राज्यीय नदी या उसमें मौजूद पानी का कोई अन्य पहलू नहीं है।"

54. यह तर्क दिया गया है कि कावेरी जल का मामला अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम से संबंधित है, जो न तो प्रविष्टि 56 और न ही सूची I की प्रविष्टि 97 में पाया जा सकता है। उस मामले में विचाराधीन अधिनियम अनुच्छेद 262 से संबंधित था और था प्रविष्टि 56 के तहत नहीं। यह आगे तर्क दिया गया है कि प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 17 के दायरे पर विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर अंतर-राज्य नदी के पानी के उपयोग पर कानून बनाने के लिए सक्षम है।, बशर्ते कि सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत अन्यथा संसद का कोई कानून न हो।

55. प्रतिवादी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि भागीरथी नदी एक राज्य नदी है, जिस पर याचिकाकर्ता टीएचडीसी की विद्युत परियोजनाएँ स्थित हैं; यह एक अंतर-राज्यीय नदी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में निकलती और समाप्त होती है और इसलिए, सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य की शक्ति के आधार पर कानून बनाया गया है। उनके अनुसार, चूंकि भागीरथी एक अंतर-राज्यीय नदी नहीं है, इसलिए उत्तराखंड राज्य के पास 'बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग' पर कर लगाने की शक्ति है और चूंकि कर उत्पादित बिजली पर नहीं है, इसलिए यह कर के अंतर्गत आता है। राज्य की विधायी क्षमता. यह तर्क दिया

गया है कि चूंकि सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य की शक्ति केवल सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ की शक्ति के अधीन है और चूंकि सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। - भागीरथी नदी,

56. मौजूदा मामले में, संसद का ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जो राज्य की पानी के उपयोग/खींचे गए पानी पर कर लगाने की शक्ति को प्रतिबंधित कर सके। सबसे पहले, अधिनियम द्वारा लगाए गए कर की प्रकृति और वह गतिविधि जिस पर प्रभाव पड़ता है, राज्य विधायिका की कर लगाने की क्षमता को और अधिक निर्धारित करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर कानून एक आर्थिक कानून है। लगाया जाने वाला कर राज्य को लोगों के कल्याण के प्रति अपने लक्ष्यों और दायित्वों को कार्य करने और पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक विशुद्ध रूप से राजस्व संग्रहण उपकरण है। संविधान की संघीय संरचना कर लगाने की शक्तियों को पूर्ण पृथक्करण प्रदान करती है राज्य और संघ. दोनों अपने-अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। राज्य की कर लगाने की शक्तियों को कम करने, या इसे सहमति या केंद्र की मंजूरी के अधीन करने का कोई भी प्रयास न केवल हमारे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ होगा, बल्कि राज्य को केंद्र में शामिल कर देगा। केंद्र और राज्य की कर लगाने की शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है और, इस प्रकार, ओवरलैपिंग की संभावना पूरी तरह से अनुपस्थित है। कोई भी व्याख्या जो केंद्र की किसी भी प्रकार की मंजूरी या सहमति को मान्यता देती है, केंद्र और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्तियों को अलग करने के संवैधानिक उद्देश्य को विफल कर देगी और राज्यों को केंद्र का उपांग बना देगी। यह ध्यान में रखना होगा कि कर सामान्य नियामक प्रविष्टियों से एक अलग मामला है। विनियामक प्रविष्टियाँ कराधान के लिए नहीं हैं। 'कर' शब्द व्यापक है और इसमें शुल्क सहित सभी प्रकार के अधिभार शामिल हैं। इसमें राज्य द्वारा सभी प्रकार की अनिवार्य निकासी शामिल है। इसलिए, इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलील पूरी तरह से गलत है।

57. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केसोराम के फैसले में

निम्नानुसार कहा है:

31. संविधान का अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का स्रोत है। यह इस संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रदान करता है। संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल के बीच विधायी क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है सातवीं अनुसूची में सूची I, जिसे 'संघ सूची' कहा जाता है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची III, जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त दोनों के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सूची II, जिसे 'राज्य सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 248 के तहत कानून बनाने की संसद की विशेष शक्ति समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले तक फैली हुई है। समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं किए गए कर को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसे ही संसद में निहित अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 18 - में उपलब्ध निर्णयों की समीक्षा पर इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा सिद्धांतों को संक्षेप में संक्षेपित और पुनः प्रस्तुत किया गया है। वे हैं-

(1) तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की 'शक्तियाँ' नहीं बल्कि कानून के 'क्षेत्र' हैं। संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूर्ण रूप से अलग करता है। कर लगाने की शक्ति में कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है और

संविधान संघ और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत देता है।

- (2) कानून के क्षेत्रों का सीमांकन किए जाने के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच असहमति का सवाल केवल उन मामलों में उठ सकता है जब दोनों कानून किसी एक के संबंध में एक ही क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। समवर्ती सूची में शामिल मामले और सीधा टकराव नजर आ रहा है. यदि एक ओर सूची II और दूसरी ओर सूची I और सूची III के बीच ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण कोई प्रतिकूलता है, तो राज्य का कानून अधिकारातीत होगा और उसे केंद्रीय कानून के लिए रास्ता देना होगा।
- (3) कराधान को विधायी क्षमता के प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है। कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। कानून के सामान्य विषयों को प्रविष्टियों के एक समूह में और कराधान की शक्ति को एक अलग समूह में निपटाया जाता है। कर लगाने की शक्ति को सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है।
- (4) सूची में प्रविष्टियाँ केवल कानून के विषय या क्षेत्र होने के कारण, उन्हें व्यापक और उदार भावना से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए, न कि संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में। प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वी. रामास्वामी, जे. को उद्धृत करने के लिए, सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यापक श्रेणियों की एक सरल गणना के माध्यम से होता है। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित मुख्य मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति में इसके विस्तार में प्रासंगिक और सहायक मामलों से संबंधित कानून भी शामिल होंगे।

(5) जहां किसी राज्य के विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, वहां सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कानून सूचियों में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है। मैं या तृतीय. यदि ऐसा होता है, तो कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तीन सूचियां बड़ी संख्या में प्रविष्टियों वाली हों, वहां उनमें कुछ ओवरलैपिंग होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करने के लिए कि कानून का दिया गया भाग किस प्रविष्टि से संबंधित है, मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना होगा। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। न्यायालय को मामले के सार को देखना होगा। मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत कभी-कभी कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधानमंडल द्वारा विधान को दिया गया नाम महत्वहीन है। संपूर्ण अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(6) कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत तभी लागू होता है जब संघ और राज्य सूची के बीच दोनों के लिए सामान्य क्षेत्र में टकराव होता है। वहां सार और सार के सिद्धांत को लागू किया जाना है और यदि विवादित कानून काफी हद तक उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आता है जिसने इसे अधिनियमित किया है, तो किसी अन्य विधानमंडल को सौंपे गए क्षेत्र में आकस्मिक अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तीन सूचियों को पढ़ते समय, सूची I को सूची III और II पर प्राथमिकता दी जाती है, और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, फिर भी, संघ सूची की प्रबलता राज्य विधानमंडल को सूची II के किसी भी

मामले से निपटने से नहीं रोकेगी, हालांकि यह संयोगवश सूची I में किसी भी आइटम को प्रभावित कर सकता है।

58. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल के बीच विधायी क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची I, जिसे 'संघ सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची III, जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त दोनों के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सूची II, जिसे 'राज्य सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 248 के तहत कानून बनाने की संसद की विशेष शक्ति समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले तक फैली हुई है। समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं किए गए कर को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसे ही संसद में निहित अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की 'शक्तियाँ' नहीं बल्कि कानून के 'क्षेत्र' हैं। संविधान अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूर्ण रूप से अलग करता है

246. कर लगाने की शक्ति में कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है और संविधान संघ और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत देता है। रिट याचिकाओं के इस समूह में, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच विरोध का सवाल ही नहीं उठता। यह केवल उन मामलों में उत्पन्न हो सकता है जब दोनों कानून समवर्ती सूची में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में एक ही क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और सीधा टकराव देखा जाता है। यदि एक ओर सूची II और दूसरी ओर सूची I और सूची III के बीच ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण कोई प्रतिकूलता है, तो राज्य का

कानून अधिकारातीत होगा और उसे केंद्रीय कानून के लिए रास्ता देना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जिससे पता चले कि संघ और राज्य की कराधान की शक्ति में ओवरलैपिंग है।

59. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डीएस पाटनी प्रस्तुत करेंगे कि इस तथ्य के मद्देनजर राज्य के खिलाफ वचनबद्ध रोक है कि वे कोई शुल्क या कर नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं और इस संबंध में आश्वासन दिया है। इस न्यायालय का ध्यान सरकार के बीच 8 फरवरी 2006 को हुए पुनः स्थापित कार्यान्वयन समझौते (आरआईए) के खंड 13 और 18.4 की ओर आकर्षित किया गया है। उत्तराखंड सरकार, जिला पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूपी, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्व में डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड)।

60. आरआईए का खंड 13 'जल उपयोग अधिकार' के संबंध में है। खण्ड 13.1 इस प्रकार है:

"13.1 जीओयू एतद्वारा कंपनी को परियोजना के लिए अलकनंदा नदी के पानी का उपयोग करने और साइट पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने और ऐसे उचित उद्देश्यों के लिए सीधे संबंधित और आवश्यक के लिए अवधि के दौरान किसी भी और सभी शुल्क से मुक्त अधिकार प्रदान करता है। इस आरआईए की शर्तों के अनुसार और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के अधीन परियोजना के लिए बिजली का उत्पादन। ऐसा अधिकार पहले कंपनी को तत्कालीन हस्ताक्षरित जल उपयोग समझौते (डब्ल्यूयूए) के तहत उपलब्ध था, जो अब प्रतिस्थापित हो गया है इस आरआईए के प्रावधानों द्वारा। जीओयू इस आरआईए की अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली पर किसी भी प्रकार का कोई कर, शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगाएगा।

61. आरआईए का खंड 18, 'मस्ट-रन प्रोजेक्ट' के संबंध में है। खण्ड 18.4 इस प्रकार है:

"18.4 जल उपयोग शुल्क का भुगतान - पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि कंपनी पर पानी के उपयोग के लिए कोई भुगतान दायित्व नहीं होगा। जीओयू आरआईए के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय इस आरआईए के तहत पानी के उपयोग के लिए शुल्क नहीं लेगा।"

62. यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यूके उनियाल ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का समर्थन किया है। इसके अलावा, श्री उनियाल का कहना है कि आरआईए के समय सरकार के बीच समझौता हुआ था। उत्तराखंड सरकार, यूपी, यूपीपीसीएल और याचिकाकर्ता एएचपीसीएल की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार। उत्तराखंड सरकार इस आरआईए की अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली पर किसी भी प्रकार का कोई कर, शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगाएगी। आरआईए के खंड 18.4 में एक विशिष्ट शर्त भी रखी गई है कि कंपनी को कोई भुगतान नहीं करना होगा पानी और सरकार के उपयोग के लिए दायित्व। उत्तराखंड सरकार आरआईए के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय इस आरआईए के तहत पानी के उपयोग के लिए शुल्क नहीं लेगी। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि पानी के उपयोग के लिए कर न लगाने की छूट देने का उद्देश्य याचिकाकर्ता को एक प्रकार की रियायत देना था ताकि वह उत्तराखंड राज्य में बिजली उत्पादन के लिए अपनी रुचि दिखा सके। ऐसी रियायत उत्तराखंड राज्य द्वारा वापस नहीं ली जा सकती और यह याचिकाकर्ता के साथ किए गए वादे के खिलाफ होगी। उनका यह भी कहना था कि बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर कर लगाने से बिजली की लागत बढ़ जाएगी जो अंततः उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। उनका कहना है कि बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर कर लगाना बिजली उत्पादन पर अप्रत्यक्ष कर लगाने के समान होगा और जब आरआईए के सभी पक्ष समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे हैं तो राज्य अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट सकता। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता एएचपीसीएल की ओर से जो तर्क दिया गया है वह सही है और विवादित अधिनियम का अधिनियमन

वचन विबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

63. उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए यह दिखाने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया कि छूट वापस लेने के माध्यम से सरकार द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी; न ही याचिकाकर्ता कंपनियों को कोई भारी नुकसान हुआ क्योंकि कर का बोझ अंततः उपभोक्ता पर डाला जाएगा।

(i) कासिका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1995) 1 एससीसी 274

(ii) अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1992) 2 एससीसी 411

(iii) पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2004) 6 एससीसी 465

64. पैराग्राफ नं. कासिका ट्रेडिंग के 13 और 27 यहां से निकाले गए हैं:

"13. प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का दायरा, दायरा और आयाम इस देश में भारत संघ बनाम इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड, एआईआर 1968 एससी से शुरू होने वाले इस न्यायालय के क्रमिक निर्णय के माध्यम से पिछली एक सदी में विकसित हुआ है। 718. इस संबंध में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद, (1970) 1 एससीसी 582: मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूपी राज्य: जीत राम शिव का संदर्भ दिया जा सकता है। कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 1 एससीसी 11: भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, (1985) 4 एससीसी 369: इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बीओएम) प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1985) 1 एससीसी 641: पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य [1986] सप्लिमेंट। एससीसी 728: श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम गुजरात राज्य, (1987) 1 एससीसी 31: सहायक। वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी, (1988) 3 एससीसी 570: अमृत बनस्पति कंपनी

लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (1992) 2 एससीसी 511 और भारत संघ बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। (1993) 3 एससीसी 499। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय ने राय दी:

"हम यह भी बता सकते हैं कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसे तब देना चाहिए जब इक्विटी की आवश्यकता हो; यदि यह सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उन्होंने किया है, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के वादे पर रोक लगाना असमान होगा, न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में इक्विटी नहीं बढ़ाएगा जिससे वादा या प्रतिनिधित्व किया गया है और सरकार या सरकार के खिलाफ वादे या प्रतिनिधित्व को लागू करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरण। ऐसे मामले में वचनबंधन का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि तथ्यों पर, समानता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व से बाध्य रखा जाए।"

वास्तव में, तथ्यात्मक स्थिति पर प्रस्तुतिकरण विवादास्पद नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष या यहां तक कि इस अपील में भी यह स्थापित करने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में है कि दिनांक 29.08.1980 की अधिसूचना किसी भी परोक्ष या बाहरी विचार के लिए जारी की गई थी और "अंदर" नहीं थी। जनहित", मामलों के पहले बैच से निपटने के दौरान हमने पहले ही जो कारण बताए हैं, उनके आधार पर उस अधिसूचना में गलती ढूंढना संभव नहीं है। अपीलकर्ताओं, जो व्यवसाय में हैं, को व्यवसाय में ज्वार के लिए तैयार रहना होगा। पौरनामी ऑयल मिल्स में, 1986 सप्प एससीसी 728, यह औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन था, जिसमें छूट दी गई थी और यह उस तथ्य की स्थिति में

था कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध रखा गया था। फिर से बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज, (1987) 1 एससीसी 31 में, यह एक अनुरूप क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन था कि छूट दी गई थी और न्यायालय ने माना कि सरकार इसके द्वारा पहले दी गई छूट को तभी वापस ले सकती है जब ऐसी वापसी हो प्रॉमिसरी एस्टोपेल के नियम का उल्लंघन किए बिना और पूरे निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट का दावा करने के हकदार उद्योग को वंचित किए बिना किया जा सकता है, जिसके लिए प्रोत्साहन देने के समय छूट का वादा किया गया था। इस मामले में जारी अधिनियम की धारा 25 में पीवीसी रेजिन का उपयोग करने के लिए किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था और दूसरी ओर, वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में जारी किया गया था और बाद में इसे वापस ले लिया गया था। जनहित में फिर से वही शक्तियां। हमारी राय में, सरकार द्वारा कार्रवाई न करने और अपनी नीति की समीक्षा न करने के स्पष्ट वादे के अभाव में अपीलकर्ताओं पर कोई उचित पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ, भले ही आवश्यकता हुई हो और "सार्वजनिक हित" की मांग की गई हो। इस प्रकार, इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता धारा 25 के तहत जारी वापसी अधिसूचना पर सवाल उठाने के लिए प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते हैं। अधिनियम का।"

65. इसके अलावा, पैराग्राफ संख्या में। अमृत बनस्पति 15 के 4 और 10 के अनुसार, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

लेकिन यह निर्विवाद है कि इस पर कार्रवाई करते हुए अपीलकर्ता के प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत रूप से राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पाया कि वह राज्य में वनस्पति विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने में रुचि रखते थे; इसलिए, इसके प्रबंधक ने जून 1968 में

मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि रियायत उपलब्ध कराई जाए, जिसका उत्तर उद्योग निदेशक ने 2 जुलाई, 1968 को दिया और अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि घोषणा के अनुसार रियायत दी जाएगी। उपलब्ध होगा और अपीलकर्ता को आगे सूचित किया जाएगा कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को तैयार है जिसकी अपीलकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान और विभिन्न बैठकें हुईं... इसके प्रबंधक ने जून 1968 में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि रियायत उपलब्ध कराई जाए, जिसके जवाब में उद्योग निदेशक ने 2 जुलाई, 1968 को अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि घोषणा के अनुसार रियायत दी जाएगी। उपलब्ध है और अपीलकर्ता को आगे सूचित किया कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को तैयार है जिसकी अपीलकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान और विभिन्न बैठकें हुईं... इसके प्रबंधक ने जून 1968 में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि रियायत उपलब्ध कराई जाए, जिसके जवाब में उद्योग निदेशक ने 2 जुलाई, 1968 को अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि घोषणा के अनुसार रियायत दी जाएगी। उपलब्ध है और अपीलकर्ता को आगे सूचित किया कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को तैयार है जिसकी अपीलकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान और विभिन्न बैठकें हुईं... 1968 ने अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि

घोषित रियायत उपलब्ध होगी और अपीलकर्ता को आगे सूचित किया कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को तैयार है जिसकी अपीलकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान और विभिन्न बैठकें हुईं... 1968 ने अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि घोषित रियायत उपलब्ध होगी और अपीलकर्ता को आगे सूचित किया कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को तैयार है जिसकी अपीलकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान और विभिन्न बैठकें हुईं...

...इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व था कि यदि वह फोकल प्वाइंट में अपनी इकाई स्थापित करता है तो वह सरकार द्वारा घोषित रियायत और प्रोत्साहन का हकदार होगा। क्या इस तरह के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप बाध्यकारी समझौता हुआ, यह अलग मुद्दा है लेकिन सरकारी नीति के अनुसरण में उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक से आने वाले प्रतिनिधित्व को अनधिकृत या अधिकार के दायरे से परे नहीं माना जा सकता है..."

10. लेकिन समानता के सिद्धांत का विस्तार होने के कारण, जिसका मूल उद्देश्य निष्पक्षता पर आधारित न्याय को बढ़ावा देना है और वादा करने वाले के अपने वादे से मुक्त होने के कारण होने वाले किसी भी अन्याय से छुटकारा दिलाना है, अदालत में लागू होने में असमर्थ है। कानून के अनुसार यदि वह वादा जो कार्रवाई का कारण बताता है या समझौता, व्यक्त या निहित, बाध्यकारी अनुबंध को जन्म देता है, वैधानिक रूप से निषिद्ध है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है...

... अधिनियम के तहत देय और कानून के अनुसार वसूले गए कर को वापस करने का वादा या समझौता संविधान

के साथ धोखाधड़ी और लोगों के विश्वास का उल्लंघन होगा। बिक्री कर जैसे करों का भुगतान एक गरीब व्यक्ति द्वारा भी अपनी बचत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और राज्य के विकास में भागीदारी की भावना से किया जाता है। राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रलोभन के रूप में भुगतानकर्ता को नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति, एक निर्माता को रिफंड के रूप में इसका उपयोग लोगों के विश्वास का उल्लंघन होगा जो कानून के तहत धोखाधड़ी के बराबर होगा।"

66. नेस्ले इंडिया⁷ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"40। अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत कासिका ट्रेडिंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1995) 1 एससीसी 274 का मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि धारा 25 जैसे राजकोषीय कानून में एक प्रावधान के तहत छूट अधिसूचना जारी करना मात्र हैसीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कोई वचनबंध रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ऐसी छूट अपने स्वभाव से ही रद्द होने या संशोधित होने या अन्य शर्तों के अधीन होने के लिए अतिसंवेदनशील होती है। दूसरे शब्दों में, कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं है। छूट देने की शक्ति में गोलमाल के बीज निहित हैं। इसलिए, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना छूट अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की याचिका को विफल करने के लिए सरकार के लिए अपने पक्ष में एक सर्वोपरि इक्विटी स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि भारत सरकार ने जनहित में प्रासंगिक कारणों पर छूट अधिसूचना को वापस लेने को उचित ठहराया था।

"सीमा शुल्क आदि का बोझ उपभोक्ता पर डाला जाता है और इसलिए अपीलकर्ताओं को भारी नुकसान होने का सवाल समझ में नहीं आता है।"

(श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1997) 3 एससीसी 398 और एसटीओ बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स, (1998) 1 एससीसी 572 भी देखें)। हम इस निर्णय की इस मामले के तथ्यों से प्रासंगिकता नहीं देखते हैं। यहां अभ्यावेदन स्पष्ट और स्पष्ट हैं।"

67. याचिकाकर्ता टीएचडीसी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा जताया। पैराग्राफ संख्या में 24, 26 और 45 में डॉ. टीएस ठाकुर, सीजे (जैसा कि उस समय लॉर्डशिप थी) ने स्वयं और सीकरी और खानविलदार, जेजे द्वारा निम्नानुसार देखा गया है:

"24। हालाँकि, संप्रभु शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, विशेष रूप से हमारी जैसी संघीय व्यवस्था में, जहाँ राज्य भी अनुमति की सीमा तक कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें कर, शुल्क और शुल्क लगाने वाले कानून भी शामिल हैं। वह शक्ति कर लगाना संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, यह अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य, (1990) 1 एससीसी 109 में माना है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही इसका आनंद लेते हैं। संप्रभु शक्ति का प्रयोग उस सीमा तक, जहां तक संविधान उन्हें वह शक्ति प्रदान करता है। इस न्यायालय ने घोषणा की:

लोगों के स्वास्थ्य, शांति, नैतिकता, शिक्षा और अच्छी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली सभी चीजें करने के लिए संप्रभु शक्ति प्रत्येक संप्रभु राज्य में पूर्ण और अंतर्निहित है। संप्रभुता को परिभाषित करना कठिन है। हालाँकि, संप्रभुता की यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। कुछ संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगाने लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।" हालाँकि, संवैधानिक सीमाओं के अधीन। कुछ

संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगान लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।" हालाँकि, संवैधानिक सीमाओं के अधीन। कुछ संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगान लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।"

26. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जब अनुच्छेद 246(2) और (3) सातवीं अनुसूची में मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडलों को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तो ऐसी विधायी शक्ति ऊपर उल्लिखित संवैधानिक सीमाओं के अधीन प्रयोग योग्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य विधानमंडलों की कर लगाने की शक्ति भी संविधान के भाग XIII में प्रदर्शित अनुच्छेद 304 (ए) की सीमाओं के अधीन है, जो भाग राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग को नियंत्रित करता है। भारत और इसमें अनुच्छेद 301 से 307 शामिल हैं। इन अनुच्छेदों के प्रावधान इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला का विषय रहे हैं, जिनमें कई संविधान पीठ के फैसले भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ का हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे। प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा और गैर-स्पष्ट धाराएं जिनके साथ एक ही शुरुआत होती है, ने पिछले पांच दशकों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कई विवादास्पद मुद्दों को जन्म दिया है।

68. उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने पैराग्राफ संख्या पर भरोसा जताया। निर्णय के 28, 29, 91 और 332 (सुप्रा) निम्नानुसार हैं:

"28. कर लगाने की शक्ति, केवल संविधान द्वारा नियंत्रित एक संप्रभु शक्ति होने के नाते, उस शक्ति पर कोई भी सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। यह प्रस्ताव उमेग सिंह बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1955 एससी में इस

न्यायालय के निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। 540 और फर्म बंसीधर प्रेमसुखदास बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1967 एससी 40। उमेग सिंह मामले में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में बताया:

"12. ...राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा ही सीमित किया जा सकता है और जब तक कि संविधान में इस विषय पर स्पष्ट रूप से या सशर्त रूप से कानून बनाने पर कोई प्रावधान नहीं है, तब तक कोई प्रावधान नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को प्राप्त पूर्ण शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमा। ...

13. राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा, जिसके पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में निर्दिष्ट विधायी प्रमुखों के दायरे में कानून की पूर्ण शक्तियां थीं, केवल संविधान द्वारा ही लगाई जा सकती थीं और किसी भी दायित्व से नहीं जो डोमिनियन सरकार या बॉम्बे प्रांत या यहां तक कि बॉम्बे राज्य द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 246 के तहत राज्य विधानमंडल को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी और यह शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 245(1) के आधार पर थी। संविधान ने स्वयं ही इस शक्ति पर बंधन या सीमाएँ निर्धारित की हैं, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 303 या अनुच्छेद 286(2)। लेकिन जब तक अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि संविधान ने स्वयं स्पष्ट रूप से या तो पूरी तरह से या सशर्त रूप से इस विषय पर कानून बनाने पर रोक लगा दी है, राज्य विधानमंडल की अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बनाने की शक्ति पूर्ण थी। एक बार जब कानून का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III की

किसी भी प्रविष्टि में शामिल हो गया, तो ऐसी विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा को संविधान के भीतर ही पाया जाना था और यदि ऐसी कोई बाधा या सीमा नहीं थी यह पाया गया कि राज्य विधानमंडल के पास विवादित अधिनियम को अधिनियमित करने की पूरी क्षमता थी, भले ही ऐसा अधिनियमन दी गई गारंटी के विपरीत था, या डोमिनियन सरकार या बॉम्बे प्रांत या यहां तक कि बॉम्बे राज्य द्वारा किए गए दायित्व के विपरीत था।

29. बंसीधर मामले (सुप्रा) में फिर से इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

यह दृष्टिकोण जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम संयुक्त प्रांत, 1946 8 एफसीआर 111 में न्यायिक समिति के फैसले से सामने आया है, जिसमें अवध के तालुकदारों द्वारा संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम (यूपी अधिनियम 17) के खिलाफ इसी तरह की शिकायत की गई थी। (1939). न्यायिक समिति द्वारा यह माना गया कि क्राउन केवल इस तथ्य से अपने विधायी अधिकार से वंचित नहीं हो सकता अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह उस क्षेत्र के भीतर भूमि का अनुदान देता है जिस पर ऐसा विधायी अधिकार मौजूद है, और कोई भी अदालत अपनी संप्रभु क्षमता के वैध दायरे में कार्य करने वाले विधायी निकाय के अधिनियमन को रद्द नहीं कर सकती है। इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि क्राउन अनुदान का विषय-वस्तु प्रांतीय विधायिका की क्षमता के भीतर है, तो उस विधायिका को इसके बारे में कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कि संविधान अधिनियम न हो। स्वयं स्पष्ट रूप से इस विषय पर पूर्ण या सशर्त रूप से कानून बनाने पर रोक लगाता है। तदनुसार, ऐसे किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में, संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1939, जो आगरा और अवध में कृषि किरायेदारी और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, विशेष विधायी क्षमता के भीतर मामलों से

निपटता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची 11 के आइटम 21 के तहत प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका के अधीन थी, भले ही इसके कुछ प्रावधानों ने अनुदान में शामिल होने के लिए अपीलकर्ता तालुकदार द्वारा दावा किए गए पूर्ण अधिकारों में कटौती की हो। उनकी संपत्ति का प्रमाण क्राउन द्वारा उनके पूर्ववर्ती को दी गई सनद से मिलता है। उमेग सिंह और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1955 एससी 540। यह बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के मद्देनजर, गारंटी पत्रों के खंड 5 की शर्तों से विधायी क्षमता में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। डोमिनियन सरकार द्वारा "राज्यों" के शासकों को दिया गया विलय के समझौतों के बाद, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विलय किए गए 'राज्यों' में जागीरों की निरंतरता की गारंटी देता था। यह सिद्धांत महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर 1963 एससी 953 में इस न्यायालय के हालिया फैसले को भी रेखांकित करता है, जिसमें यह बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 295 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद को कानून बनाने से रोकता है। किसी अनुबंध या अनुदान के नियमों और शर्तों को बदलने वाला कानून जिसके तहत भारत सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है..." (जोर दिया गया)

91. यह कहना पर्याप्त है कि संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या तभी सही और सही होगी जब न्यायालय संविधान को समग्र रूप से देखता है और संवैधानिक योजना की सभी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखता है और लगातार खुद को इसकी आवश्यकता की याद दिलाता है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, ऐसा न हो कि किसी दिए गए प्रावधान पर की गई व्याख्या संविधान के किसी अन्य प्रावधान या विशेषता के प्रभाव या महत्व को कम करने या कम करने का प्रभाव डाले। इस प्रकार व्याख्या की गई कि भाग XIII में प्रदर्शित अनुच्छेद 301, हमारी राय में, राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर बाधा के रूप में

काम नहीं करता है, सिवाय उन स्थितियों के जहां ऐसे कर अनुच्छेद 304 (ए) के उल्लंघन में आते हैं। संविधान का इस प्रकार प्रासंगिक दृष्टिकोण उस पाठ्य व्याख्या से पूरी तरह मेल खाता है जिसे हमने भाग XIII में रखा है।"

332. उपरोक्त संविधान सभा की बहस और अनुच्छेद 301 का इतिहास बताता है कि अनुच्छेद 301 में परिकल्पित स्वतंत्रता करारधान से मुक्ति नहीं है बल्कि केवल व्यापार बाधाओं से मुक्ति है। जब तक कर गैर-भेदभावपूर्ण रहेगा, तब तक इसकी वैधता को अनुच्छेद के तहत नहीं आंका जा सकता

301. संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत, एक राज्य के पास सातवीं अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 246(3) अनुच्छेद 246 के खंड (1) और (2) के अधीन है, यानी सातवीं अनुसूची की सूची I और III में सूचीबद्ध मामले। अनुच्छेद 265 के अनुसार, कर केवल कानून के अधिकार के तहत लगाया जा सकता है और इसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। करारधान में अनुच्छेद 366(28) के तहत परिभाषित किसी भी कर को लगाना शामिल है :

"366(28) "करारधान" में किसी भी कर या लगान को लगाना शामिल है, चाहे वह सामान्य हो या स्थानीय या विशेष, और "कर" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।"

यह कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी बोझ के एक हिस्से के रूप में अनिवार्य वसूली की एक संप्रभु शक्ति है। कर लगाना करदाताओं को किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए की गई एक अनिवार्य वसूली है।"

69. सबसे पहले, इस न्यायालय को इस मुद्दे से निपटना होगा - क्या सरकार। क्या उत्तराखंड सरकार आक्षेपित

अधिनियम को लागू करने के लिए वचनबंधन से बंधी है? पार्टियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और कासिका ट्रेडिंग 13, अमृत बनस्पति 15 और नेस्ले इंडिया लिमिटेड 7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि राज्य सरकार की कार्रवाई उचित है। वचन विबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं।

70. इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में सरकार के खिलाफ रोक का सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो विधायिका को एस्टोपेल के सिद्धांत का सहारा लेकर अपने विधायी कार्य करने से कभी नहीं रोका जा सकता है। यह प्रस्ताव असाधारण है, क्योंकि सरकार का जनता के प्रति एक विशेष तरीके से कार्य करने का कर्तव्य है और सरकार को कानून के तहत अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए रोक के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। वचन-बंधन के नियम को कानून के प्रावधानों को विफल करने के लिए दलील नहीं दी जा सकती। विबंध का सिद्धांत कानून द्वारा लगाए गए दायित्व या दायित्व के तहत लागू नहीं किया जा सकता है,

71. इस न्यायालय के विचारार्थ दूसरा मुद्दा यह है कि क्या राज्य विधायिका विवादित अधिनियम को लागू करने में सक्षम है या नहीं?

72. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता और अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी है कि चूंकि राज्य सरकार ने स्वयं याचिकाकर्ता कंपनियों के साथ एक आरआईए में प्रवेश किया है, इसलिए यूपी राज्य और यूपीपीसीएल और आरआईए को निष्पादित किया गया है। पार्टियों के बीच, उनकी कार्रवाई वचनबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। साथ ही, चुनौती संवैधानिक वैधता और अधिनियम की शक्तियों पर भी है राज्य की विधायी क्षमता. जहां तक एएचपीसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ यूपीपीसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का सवाल है, इस निर्णय के मुख्य भाग में इस संबंध में तथ्यों और कानून पर चर्चा करते हुए विस्तृत टिप्पणियां की गईं

हैं और यह माना गया है कि अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकार की कार्रवाई वचनबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं है। जहां तक राज्य की विधायी क्षमता का सवाल है, याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 288 के मद्देनजर कोई अधिकार नहीं देता है।

73. भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 निम्नानुसार प्रदान करता है-

"200. विधेयकों पर सहमति - जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया हो या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो यह होगा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उस पर सहमति रोकता है या वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करता है:

बशर्ते कि राज्यपाल बिल को सहमति के लिए प्रस्तुत करने के बाद जितनी जल्दी हो सके, बिल को वापस कर सकते हैं यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो यह अनुरोध करते हुए एक संदेश के साथ कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे। और, विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेगा जैसा कि वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और, जब कोई विधेयक लौटाया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन द्वारा फिर से पारित किया जाता है या सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन के और राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोकेंगे:

बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति नहीं देंगे, बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेंगे, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों से इतना कम

हो जाएगा कि स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। वह न्यायालय इस संविधान द्वारा भरने के लिए बनाया गया है।"

74. इसके अलावा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 निम्नानुसार निर्धारित है:

"288. कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से छूट। - (1) जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा प्रदान कर सकते हैं, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू राज्य का कोई भी कानून नहीं होगा किसी भी मौजूदा कानून या किसी अंतर-राज्यीय नदी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, उत्पादित, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली के संबंध में कर लगाना या लगाने का अधिकार देना। नदी की घाटी।

स्पष्टीकरण। - इस खंड में अभिव्यक्ति "किसी राज्य के लागू कानून" में इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाया गया एक राज्य का कानून शामिल होगा और पहले निरस्त नहीं किया गया होगा, भले ही यह या इसके कुछ हिस्से तब लागू न हों। सभी या विशेष क्षेत्रों में।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा खंड (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे कर को लगा सकता है, या लगाने का अधिकार दे सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी कानून का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि वह विचार के लिए आरक्षित न कर दिया गया हो। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई; और यदि ऐसा कोई कानून किसी प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर की दरों और अन्य घटनाओं के निर्धारण के लिए प्रदान करता है, तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। ऐसा कोई नियम या आदेश।"

75. भारत के संविधान के अनुच्छेद 288 में निहित प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि कर किसी मौजूदा कानून या किसी कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, उत्पादित, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली के संबंध में नहीं है। किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया। बल्कि, यह बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर-उपभोग्य उपयोग पर एक कर है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 288(1) के अंतर्गत नहीं आता है। जहां तक याचिकाकर्ता टीएचडीसी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का एक और तर्क है कि अनुच्छेद 288(2) में निहित प्रावधान के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधायिका ऐसा कोई कर तभी लगा सकती है जब कानून को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 288(2) का उल्लंघन नहीं है। बल्कि यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप है। सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को विधेयक के अधिनियम का रूप लेने से पहले संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, अनुच्छेद 163(2) संविधान में प्रावधान है - यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला है या नहीं, जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 200 को पढ़ने से पता चलता है कि चूंकि मामला सूची II की प्रविष्टि 17 से संबंधित है जिसके तहत राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, इस प्रकार राज्य विधायिका द्वारा विधेयक के अनुमोदन के बाद, माननीय राज्यपाल ने सहमति दे दी है उपरोक्त विधेयक के लिए इस अनुच्छेद के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए। साथ ही, चूंकि मामला सूची I (संघ सूची) से

संबंधित नहीं है, इसलिए उपरोक्त विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 288 के उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलें गलत हैं।

76. यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि राज्य विधानमंडल उत्तराखंड राज्य में गैर-उपभोग्य उपयोग के लिए पानी पर कर लगाने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता है, इसलिए, इसमें किसी प्रावधान के अभाव में संबंध में, प्रश्नगत अधिनियम में कोई दोष नहीं जोड़ा जा सकता है।

77. याचिकाकर्ता मेसर्स स्वस्ति पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी। लिमिटेड ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी राज्य उसकी दलीलों के विपरीत बहस नहीं कर सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी राज्य ने उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा की गई दलीलों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। दिनांक 11.06.2018 को दायर जवाबी हलफनामे में रिट याचिका संख्या. 2018 के 641 (एम/एस), पैराग्राफ 28(ई) में प्रतिवादी राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि:

"उक्त अधिनियम 2012, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियमित किया गया है, जो राज्य सूची (सूची II) से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता से संबंधित है। इसके अलावा, विधेयक पारित हुआ राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 288(2) के तहत इसे एक अधिनियम बनाने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 और 163(2) के तहत सहमति दे दी गई है।"

जवाबी हलफनामे के उक्त पैराग्राफ पर भरोसा करते हुए यह कहा गया है कि प्रतिवादी राज्य अचानक अंतिम तर्क के चरण में जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से अलग हो गया है और तर्क उठाए हैं, जो उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। जवाबी हलफनामा. इस तरह की दलीलें अधिनियम के कथन और

उद्देश्यों और विवादित अधिनियम पर 14.12.2011 को हुई विधायी बहस के भी विपरीत हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अंतिम तर्क के चरण में उत्तरदाताओं ने पहली बार यह तर्क उठाया है कि विवादित अधिनियम सूची II की प्रविष्टि 17, 18, 45, 49 और 50 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया है, जो इसके विपरीत है। जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा जो दलीलें दी गईं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी राज्य द्वारा दिनांक 11.06.2018 को जवाबी हलफनामा श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार के माध्यम से दायर किया गया था, जो राज्य के विधिवत प्रतिनिधि नियुक्त हैं। इसलिए, प्रतिवादी राज्य अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से किए गए प्रस्तुतीकरण का पूरी तरह से खंडन करके, अंतिम तर्क के इतने विलंबित चरण में एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं प्रतिवादी राज्य अंतिम दलीलों के इतने विलंबित चरण में, अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से की गई दलीलों का पूरी तरह से खंडन करके, एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं प्रतिवादी राज्य अंतिम दलीलों के इतने विलंबित चरण में, अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से की गई दलीलों का पूरी तरह से खंडन करके, एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं तर्क विवादित अधिनियम को लागू करने के पीछे के विधायी इरादे के भी विपरीत हैं, जैसा कि विवादित अधिनियम पर विधायी बहस में दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सूची II की प्रविष्टि 17 से विवादित अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी क्षमता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, प्रतिवादी राज्य को जवाबी हलफनामे में उसके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ विवादित अधिनियम के पीछे के विधायी इरादे के विपरीत इतनी देर से अपने तर्कों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"27. अधिनियम पूरी तरह से एक अलग स्तर पर खड़ा है और उच्च न्यायालय के दिनांक 19.04.2001/24.04.2001 के फैसले का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। अधिनियम यह उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतंत्र है और इसकी वैधता का परीक्षण इन आधारों पर नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के समर्थन में पिछली कार्यवाही और वर्तमान कार्यवाही में कथित तौर पर राज्य द्वारा उठाए गए अलग-अलग रुख पर दृढ़ता से भरोसा किया है। संजीव कोक एमएफजी कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1983) 1 एससीसी 147 में इस न्यायालय ने माना है कि कानून की वैधता का आकलन राज्य की ओर से दायर एक हलफनामे में कही गई बातों से नहीं किया जाना चाहिए और यह कि यह गिरना चाहिए या अपने प्रावधानों के बल पर खड़ा होना चाहिए।"

79. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर बहुत जोर दिया गया है। शुरू में श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव (सिंचाई), सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में सत्ता प्राप्त करने का स्रोत उत्तराखंड का बताया गया है, लेकिन बाद में एक और जवाबी हलफनामा दाखिल कर राज्य ने अपने रुख में भारी बदलाव किया है। यह सत्य है कि राज्य ने एक और हलफनामा दायर करके अपना बचाव बदल दिया है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ आधारों पर कानून की वैधता पर हमला किया गया है, केवल याचिकाकर्ताओं को ही अधिनियम की वैधता पर हमला करना होगा। और उन्हें दलील उठाकर और कानून के प्रावधानों की व्याख्या करके यह साबित करना होगा कि इसे लागू करना राज्य की क्षमता से परे है। अनुचित जवाबी हलफनामा दाखिल करना या जवाबी हलफनामे में कोई विशिष्ट दलील न उठाना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के मामले में, जवाबी हलफनामे की अधिक

प्रासंगिकता नहीं है। यह याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वे कानूनी टिकाऊ आधारों पर अधिनियम की वैधता पर हमला करें।

80. याचिकाकर्ताओं मेसर्स स्वस्ति पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक और दलील दी गई। लिमिटेड और टीएचडीसी का मानना है कि विवादित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत निहित याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कहा गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन यह कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। हालांकि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा अर्थात् (i) कि वर्गीकरण होना चाहिए एक समझदार अंतर पर स्थापित किया गया है जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और (ii) उस अंतर का उस वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि बिजली पैदा करने के उद्देश्य से खींचे गए पानी पर कर लगाने और लगाने के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उन पर दोगुना कर लगाया जा रहा है, जिससे यह दोहरे कराधान के अधीन हो रहा है। पनबिजली परियोजनाओं से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% मुफ्त बिजली के अनुदान के रूप में रायल्टी का भुगतान और उसके बाद लागू अधिनियम के अनुसार जल कर का भुगतान करके।

81. जहां तक विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील है कि विवादित अधिनियम असंवैधानिक है, जहां तक यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, वर्तमान बैच के अन्य याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा लागू अधिनियम के तहत उल्लंघन किया गया है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी

भेदभाव, अनुचित वर्गीकरण या समानता खंड के स्पष्ट उल्लंघन का सुझाव देता हो। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है संविधान का संबंध है, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित अधिनियम के जारी होने से केवल पानी पर कर समान रूप से और तर्कसंगत रूप से लागू किया गया है और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या धारण करने की स्वतंत्रता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के कोई भी अधिकार नहीं हैं। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का उल्लंघन किया गया है। अधिनियम अधिनियम के तहत परिभाषित जल स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिए पानी पर उपयोग शुल्क वसूलने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 राज्य सरकार को पानी के उपयोग पर शुल्क / कर / उपकर / कानून बनाने का अधिकार देती है। चूंकि उत्तराखंड मुख्य रूप से सीमित राजस्व संसाधनों वाला एक पहाड़ी नकदी-भूखा राज्य है, इसलिए, राज्य की नदियों के पानी का उपयोग करने वाले सभी लोगों पर एक समान कर लगाया गया है। इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भागीरथी और अलकनंदा नदी। अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अलावा कहीं भी बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि यह बिजली उत्पादन के लिए पानी (गैर-उपभोग्य) के उपयोग पर कर लगाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में दी गई दलीलों पर गौर करने से पता चलता है कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि लागू अधिनियम किस तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जो कोई भी यह कहता है कि किसी भी अधिनियम के प्रावधान उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर प्रदर्शन करने का भारी कर्तव्य है किस प्रकार से इस तरह का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में विशिष्ट दलीलों के अभाव में यह माना जाएगा कि अधिनियम किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों में कोई दम नहीं

है।

82. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीके कोहली और श्री डीएस पाटनी यह प्रस्तुत करेंगे कि उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना, मनमाना होना, राज्य की कार्यवाही में मनमानी प्रकट करना, प्रतिवादी राज्य की रंगीन शक्तियों के प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है। और राज्य के पास बिजली उत्पादन पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। एमपी सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन 6 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ 14, 15, 16 और 17, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, यहां उद्धृत किया गया है:

"14. 1981 के अधिनियम में संशोधन द्वारा प्रस्तुत धारा 3 की उप-धारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपकर की उगाही "उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर" थी। वाक्यांश "चाहे बिक्री के लिए हो या आपूर्ति के लिए" केवल यह स्पष्ट किया गया है कि अपने गंतव्य की परवाह किए बिना उत्पादित सभी बिजली निर्दिष्ट दर पर उपकर के लिए उत्तरदायी होगी। "ऊर्जा उत्पादित" वाक्यांश के बाद "चाहे" शब्द का उपयोग करने का मतलब है कि उपकर उत्पादित इकाइयों पर लागू होगा, चाहे उल्लिखित विकल्पों में से जो भी हो शब्द "चाहे" के बाद, अर्थात्, बिक्री या आपूर्ति या उपभोग का मामला है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इस्तेमाल किए गए शब्द विधायिका के इरादे को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

इस अधिरोपण की परिकल्पना बिजली इकाइयों के उत्पादन पर की गई थी। यह शुल्क उत्पादन पर था न कि बिजली की बिक्री या खपत पर। विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3 में प्रयुक्त भाषा और वास्तव में उसी की धारा 3(1) में प्रयुक्त भाषा से एक सचेत भाषाई विचलन है। अधिनियम जहां विद्युत ऊर्जा के वितरकों द्वारा बेची या आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर उपकर लगाया जाता है। उसी धारा की उप-धारा (2) के तहत उत्पादकों के साथ व्यवहार करते समय, "उत्पादित

विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर" उपकर का भुगतान करना आवश्यक है। यदि, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है, धारा (1) और उपधारा (2) के तहत लेवी की घटना समान थी, तो दोनों उपधाराओं में एक ही भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए था। जहां तक उत्पादकों का सवाल है, भाषा में जानबूझकर किया गया बदलाव लेवी की विषय-वस्तु को बदलने के इरादे को दर्शाता है।

15. धारा 3 की उपधारा (2) की हमारी व्याख्या उक्त उपधारा के परंतुक की भाषा और प्रभाव के अनुरूप है। यह माना गया है कि परंतुक का सामान्य कार्य अधिनियम से बाहर किसी चीज़ को छोड़ना या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को योग्य बनाना है जो कि परंतुक के अलावा अधिनियम के दायरे में होगा। धारा 3(2) का प्रावधान पांच मामलों में उपकर के भुगतान से "उत्पादित विद्युत ऊर्जा" को बाहर करता है। इससे पता चलेगा कि धारा 3(2) का सामान्य अनुप्रयोग, जिसमें परंतुक द्वारा एक अपवाद बनाया जा रहा था, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में था। क्या यह धारा 3(2) के परंतुक में अपवाद के लिए नहीं था, जो कर के अधीन होगा वह प्रावधान के तहत उल्लिखित पांच श्रेणियों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा होगी। यद्यपि श्रेणियों में (i), (ii), (iii) और (v) छूट उत्पादित विद्युत ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में दी गई है, अपवाद के तहत (iv) महत्वपूर्ण रूप से, पंजीकृत ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा उत्पादित सभी विद्युत ऊर्जा मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत छूट दी गई है। धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक और धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के बीच भाषा का अंतर भी बता रहा है। उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत, अपवाद निर्दिष्ट प्राधिकारियों को बेची या आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का है।

16. विधानमंडल का इरादा बिजली के उत्पादन पर उपकर लगाने का था, यह उस अधिनियम के साथ आए उद्देश्यों

और कारणों के विवरण से भी पता चलता है जिसने अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया था। इसे कहते हैं:

"उत्पादकों द्वारा अपने कैप्टिव पावर प्लांटों/डीजल उत्पादन सेटों से उत्पादित बिजली पर स्वयं उपभोग के लिए या सभी उत्पादित बिजली इकाइयों पर 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिक्री के लिए उपकर लगाने की दृष्टि से, इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।" मध्य प्रदेश उपकार अधिनियम, 1981 (1982 का 1) उपयुक्त रूप से।"

17. इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संशोधन द्वारा बिजली उत्पादन पर लेवी लगाने की मांग की गई थी, एक लेवी जिसे राज्य ने स्वीकार किया था कि वह लगाने में अक्षम था।

83. अब इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या विवादित अधिनियम दुर्भावनापूर्ण है या राज्य की विधायी शक्तियों का रंगीन प्रयोग है, जब यह आरआईए समझौते में या अन्यथा, याचिकाकर्ताओं के साथ पूर्व में हस्ताक्षर किए गए वादे को खत्म कर देता है। अधिनियम के प्रारंभ के लिए?

84. केसी गजपति नारायण देव 22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रंगीन कानून के सिद्धांत के दायरे और अर्थ की जांच करते हुए निम्नानुसार माना है:

"9. शुरुआत में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि रंगीन कानून के सिद्धांत में विधायिका की ओर से 'सच्चाई' या 'दुर्भावना' का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। संपूर्ण सिद्धांत स्वयं को सक्षमता के प्रश्न में हल करता है। किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए किसी विशेष विधायिका का। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, यदि विधायिका में योग्यता का अभाव है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता है बिल्कुल भी। कोई कानून संवैधानिक है या नहीं, यह हमेशा सत्ता का प्रश्न है। हालाँकि, एक अंतर, एक ऐसी विधायिका के बीच मौजूद है

जो ब्रिटिश संसद की तरह कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान है और उसके द्वारा प्रख्यापित कानूनों को अक्षमता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, और एक विधायिका जिसे केवल एक सीमित या योग्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यदि किसी राज्य का संविधान विधायी शक्तियों को विभिन्न निकायों के बीच वितरित करता है, जो विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों द्वारा चिह्नित अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करना होगा, या यदि मौलिक अधिकारों के रूप में विधायी प्राधिकार पर सीमाएं हैं, तो सवाल उठता है कि क्या किसी विशेष मामले में विधायिका के पास है या नहीं। कानून की विषय-वस्तु या इसे अधिनियमित करने की विधि में, इसकी संवैधानिक शक्तियों की सीमा का उल्लंघन किया गया है। ऐसा अपराध स्पष्ट, प्रकट या अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन यह प्रच्छन्न, गुप्त और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और यह मामलों के इस बाद वाले वर्ग के लिए है कि अभिव्यक्ति "रंगीन कानून" को कुछ न्यायिक घोषणाओं में लागू किया गया है। अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त विचार यह है कि यद्यपि स्पष्ट रूप से एक विधायिका एक कानून पारित करने में अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है, फिर भी सार रूप में और वास्तव में इसने इन शक्तियों का उल्लंघन किया, उचित परीक्षण करने पर यह अपराध केवल उपस्थिति या भेष के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि ओंटारियो बनाम पारस्परिक बीमाकर्ताओं और अन्य के लिए अटॉर्नी-जनरल में डफ जे. द्वारा कहा गया था, 1924 ए सी 328 पृष्ठ पर। 337 (बी):

"जहां कानून बनाने का अधिकार सीमित या योग्य चरित्र का है, वहां विधायिका वास्तव में क्या कर रही है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून के सार की कुछ सख्ती से जांच करना आवश्यक हो सकता है।" दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम का सार है जो भौतिक है न कि केवल रूप या बाहरी रूप, और यदि विषय-वस्तु वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर कानून बनाना उस विधायिका की शक्तियों से परे है, तो वह स्वरूप जिसमें कानून का ढाँचा उसे निंदा से नहीं बचाएगा। विधायिका अप्रत्यक्ष तरीका अपनाकर संवैधानिक निषेधों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस तरह के मामलों में, जांच हमेशा चुनौती दिए गए कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र के बारे में होनी

चाहिए और यह ऐसी जांच का परिणाम है, न कि केवल उसका स्वरूप जो यह निर्धारित करेगा कि यह उस विषय से संबंधित है या नहीं जो इसके अंतर्गत आता है। विधायी प्राधिकारी की शक्ति. इस जांच के प्रयोजन के लिए अदालत निश्चित रूप से कानून के प्रभाव की जांच कर सकती है और इसके उद्देश्य पर विचार कर सकती है, उद्देश्य या डिज़ाइन. लेकिन ये केवल अधिनियम के वास्तविक चरित्र और सार और कानून के विषयों के वर्ग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, जिनसे यह वास्तव में संबंधित है, न कि उन उद्देश्यों का पता लगाने के लिए जिन्होंने विधायिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।

कैनेडियन संविधान पर अपने सुप्रसिद्ध कार्य में लेफ़्ज़ॉय द्वारा कहा गया है कि भले ही विधायिका किसी अधिनियम के आरंभ में यह स्वीकार करती है कि वह किसी ऐसे विषय के संदर्भ में कानून बनाने का इरादा रखती है जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी यदि कानून के अधिनियमित खंड अधिनियम कानून को अपनी शक्तियों के भीतर लाता है, अधिनियम को 'अल्ट्रा वायर्स' नहीं माना जा सकता है।"

85. अधिनियम को पढ़ने से पता चलता है कि लगाए गए कर की प्रकृति 'बिजली उत्पादन' पर नहीं बल्कि 'पानी के उपयोग' या कहें 'बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी' पर है। 'पानी खींचा गया' शब्द का अर्थ बिजली उत्पादन के लिए पानी का वास्तविक उपयोगकर्ता है। कर का भार जल निकालने या उसके उपयोगकर्ता की गतिविधि पर है न कि उत्पादन पर। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन यह स्थापित करता है कि कर की घटना, जैसा कि धारा 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18 और 19 में परिकल्पित है बिजली पैदा करने के लिए खींचे गए पानी/उपयोग पर स्पष्ट रूप से असर पड़ता है। बिजली का उत्पादन केवल उपयोगकर्ता के प्रकार की पहचान करता है, यानी बिजली उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता। यह केवल इस उपयोग को अन्य उपयोगों से अलग करने के लिए है जिन पर कर नहीं लगाया जाना है। यदि यह कर बिजली उत्पादन पर लगाया जाना था तो विधायिका सौर या पवन उत्पादन जैसी अन्य प्रकार की बिजली पीढ़ियों

को छूट नहीं दे सकती थी। इसे "उपयोगकर्ता द्वारा खींचा गया पानी" और "बिजली का उत्पादन" वाक्यांश के बीच 'के लिए' शब्द के उपयोग से भी स्पष्ट किया जाता है। यह एक बार फिर दर्शाता है कि कर बिजली उत्पादन के लिए पानी खींचने की गतिविधि पर है।, (आई) और (एच)। अतः कानून बनाने में विधायिका की योग्यता वर्तमान मामले में पूरी तरह साबित हो गई है। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। कोई कानून संवैधानिक है या नहीं यह हमेशा सत्ता का प्रश्न है। अधिनियम का सार भौतिक है न कि रूप या बाहरी दिखावट। एक बार जांच के बाद अदालत अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य या डिज़ाइन पर विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचती है तो यह निश्चित रूप से अधिनियम के वास्तविक चरित्र और सार का पता लगा सकती है और जिन उद्देश्यों ने विधायिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया वह विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार,

86. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने न तो निकाले गए पानी को मापने के लिए परिसर के भीतर कोई प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित किया था और न ही उपयोग किए गए पानी की मात्रा को मापने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया था; और प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए व्यय को समायोजित करने के लिए कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं किया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना विवादित नोटिस जारी किया गया था।
87. आगे की चर्चा से पहले विवादित अधिनियम की धारा 14 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। खींचे गए पानी का आकलन करने की प्रक्रिया के लिए अधिनियम की धारा 14 . 1। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"आयोग योजना के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करेगा या स्थापित कराएगा जहां आयोग बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी को मापने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त

समझे या खींचे गए पानी के आकलन के लिए कोई अप्रत्यक्ष विधि अपना सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा।"

88. अधिनियम की धारा 14.2 निम्नानुसार प्रदान करती है:

"आयोग या तो अपने परिसर में या अपने स्थान पर या आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित कर सकता है या स्थापित करने की आवश्यकता कर सकता है और उसके बाद ऐसे द्वारा किए गए व्यय को समायोजित कर सकता है। ऐसी स्थापना पर उपयोगकर्ता को जल कर देय होगा।"

89. जहां तक प्रवाह मापने वाले उपकरण की स्थापना का सवाल है, अधिनियम की धारा 14 तीन विकल्प निर्धारित करती है:

(ए) आयोग स्वयं इसे योजना के परिसर में स्थापित कर सकता है;

(बी) कमीशन के कारण उपयोगकर्ता द्वारा उपकरण स्थापित किया जा सकता है, साथ ही लागत को भुगतान किए जाने वाले कर के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी; और

(सी) यह खींचे गए पानी के आकलन के लिए कोई भी अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकता है, इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14.1 और 14.2 आयोग के लिए प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करना अनिवार्य बनाती है।

90. धारा 14 के तहत आयोग द्वारा "प्रवाह मापने वाले उपकरणों" को स्थापित नहीं किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं का दावा अधिनियम का 14.1 उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी के मूल्यांकन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाने के तीसरे विकल्प में आता है। यह विधि आयोग के विवेक पर छोड़ दी गई है। जब याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों में निकाले गए पानी या वर्तमान उपयोगकर्ता के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करने और प्रदान करने में विफल रहे, तो आयोग

के पास उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी और कर का सर्वोत्तम निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। देय, पिछले वर्षों के प्रासंगिक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के आधार पर, देय कर की गणना में भरोसा करने वाले सभी कारकों का खुलासा करते हुए, उपयोगकर्ताओं को नोटिस भेजे गए थे। याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि मूल्यांकन अनंतिम हैं और अंतिम नहीं हैं। ये नोटिस 30 तारीख के आदेश में नोडल कार्यालय नियुक्त किए गए अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए गए थे। 10.2015. इस आदेश में आगे की कार्रवाई के लिए शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन भी शामिल है। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

91. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का यह भी तर्क है कि आज तक राज्य आयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (बी) के साथ पढ़ी गई धारा 20 के तहत आवश्यक है, स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए, के कार्य धारा 12 के तहत इकाइयों का पंजीकरण या उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी का मूल्यांकन, कर की गणना या अधिनियम की धारा 14, 17, 18 और 19 के तहत इसका अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।

92. अधिनियम की धारा 2(बी) को संशोधन अधिनियम संख्या द्वारा संशोधित किया गया था। 4, 2016 के माध्यम से, जिसके द्वारा उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 (2016 के संशोधन अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधित) की धारा 3 के तहत गठित "आयोग" को "आयोग" के रूप में अपनाया या शामिल किया गया था। कार्यवाही करना। धारा 20(1) स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति पर विचार करती है जहां आयोग की स्थापना समय पर नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में, प्रमुख सचिव/सचिव (सिंचाई) को अधिनियम के तहत आयोग के सभी कार्यों का निर्वहन करना था। इस संबंध में धारा 20(1) के प्रावधान के तहत आदेश दिनांक 30.10.2015 जारी किया गया था। प्रमुख सचिव (सिंचाई), सरकार की नियुक्ति। उत्तराखंड आयोग के कार्यों का निर्वहन करने के लिए। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि एक

प्राधिकरण था जो आयोग के सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम के तहत कार्यात्मक था। इस प्रकार, इकाइयों द्वारा खींचे गए पानी का मूल्यांकन और धारा 12 के तहत उनका पंजीकरण ; धारा 14 से 19 के तहत कर का निर्धारण और गणना तथा उसकी वसूली आयोग की अनुपस्थिति में भी कानूनी रूप से की जा सकती है।

93. यूपीपीसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यूके उनियाल ने इस न्यायालय का ध्यान 8 फरवरी 2006 के आरआईए के खंड 17 की ओर आकर्षित किया, जो "बिजली की डिलीवरी" से संबंधित है। आरआईए के खंड 17.1 में कहा गया है कि सरकार। उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% निःशुल्क पाने का हकदार होगा। जीओयूपी/यूपीपीसीएल और कंपनी इस बात पर सहमत हैं कि यह 12% मुफ्त बिक्री योग्य ऊर्जा कंपनी द्वारा जीओयू को उस 12% बिक्री योग्य ऊर्जा के बदले में आपूर्ति की जाएगी जो पहले कंपनी द्वारा जीओयूपी/यूपीएसईबी को मुफ्त आपूर्ति की जानी थी। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि सरकार। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तराखंड को राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बदले रॉयल्टी के रूप में 12% बिक्री योग्य ऊर्जा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

94. यूपीपीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील में कोई दम नहीं है। जहां तक उत्तराखंड राज्य को 12% बिक्री योग्य ऊर्जा उपलब्ध कराने का सवाल है, इसे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के बिजली और लाभ साझाकरण फार्मूले में प्रदान किया गया है। जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के कारण होने वाले संकट के मुआवजे के लिए भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.11.1990, जबकि अधिनियम के अनुसार पानी के उपयोग पर कर की वसूली उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए है। यह रिकॉर्ड में आया है कि राज्य ने बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर समान कर लगाया है, यहां तक कि बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार अपने स्वयं के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी, और इस प्रकार, किसी भी तरह से अनुबंध के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। . इस के

अलावा, इसलिए, बिजली उत्पादन के प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग करने वाले सभी लोगों पर एक समान कर लगाने की आवश्यकता बहुत कम है।

95. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु यह है कि लगाया गया कर उपयोग किए गए पानी की मात्रा पर आधारित नहीं है, बल्कि बांध की विभिन्न हेड ऊंचाई पर प्रति घन मीटर के आधार पर पानी के प्रवाह दर पर आधारित है। बिजली उत्पादन के उद्देश्य से. यह तर्क दिया गया है कि विवादित अधिनियम में कर की दरों के अवलोकन से पता चलेगा कि यह सीधे तौर पर मुखिया की ऊंचाई से संबंधित है। कर लगाने के आधार के रूप में, बिजली उत्पादन के लिए संग्रहीत और उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि कर का उद्ग्रहण केवल इस आधार पर आधारित है कि 'उच्च हेड, उपयोग किए गए पानी की समान मात्रा के लिए उतनी अधिक बिजली उत्पन्न होगी'। इस प्रकार, लेवी पानी के उपयोग पर नहीं बल्कि उत्पादित बिजली की मात्रा पर है। यह सिर की ऊंचाई पर निर्भर करता है और इसका 'पानी के उपयोग' से कोई संबंध नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि हेड की ऊंचाई उत्पन्न बिजली की इकाइयों की संख्या के सीधे आनुपातिक है, जितना अधिक हेड, उतनी अधिक बिजली की इकाइयां उत्पन्न होंगी। हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है पानी के उपयोग के

साथ सहसंबंध और इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। यह एक सामान्य सिद्धांत है कि सिर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतनी अधिक यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। दूसरी ओर, कम ऊंचाई वाले निचले हेड से उपयोग किए जाने वाले पानी से कम यूनिट बिजली पैदा होगी। इस प्रकार, कराधान में भेदभाव उचित और उचित है। इसलिए, राज्य द्वारा लगाया गया कर बिजली उत्पादन पर कर है न कि पानी के उपयोग पर।

96. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, इसका सार और सार, कर योग्य घटना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर ही देखा जा सकता है। धारा 2(एफ), 2(जी) और 2(i) का एक स्पष्ट पाठ, धारा 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18 और 19 के साथ पढ़ा जाए। अधिनियम से पता चलेगा कि कर 'बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी' के संबंध में है, जैसे कि लेवी इसके उपयोगकर्ता द्वारा पानी खींचने की गतिविधि पर है। इसमें कहा गया है कि केवल पानी के ऐसे उपयोगकर्ता पर कर लगाया जाना चाहिए, जो केवल और केवल बिजली उत्पादन के लिए पानी खींच रहा है। पानी निकालते ही टैक्स लगा दिया जाता है। यह मुख्य रूप से किसी भी जल स्रोत से पानी खींचने के लिए उपयोगकर्ता पर लगाया जाने वाला कर है। किसी को विधायिका की मंशा को नहीं भूलना चाहिए कि कर का विषय 'पानी का उपयोगकर्ता' है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन कर का भार केवल पानी खींचने पर पड़ता है, बिजली उत्पादन पर नहीं। इस प्रकार, राज्य विधायिका ने सही ढंग से 'पानी प्रति घन मीटर खींचे जाने पर पैसा' बना दिया है अधिनियम लागू करते समय कर का माप, न कि 'उत्पादित बिजली की इकाइयाँ'। राज्य विधायिका बिजली उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले विभिन्न बांधों की विभिन्न हेड ऊंचाई के आधार पर प्रति घन मीटर के आधार पर पानी के प्रवाह दर पर कर लगाने की अपनी क्षमता में है।

97. भानुमति³ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने इस बिंदु पर जोर दिया कि न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर कैसे विचार करना

चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ 82 से 86 यहां दिए गए हैं:

"82 बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड 11 में, इस न्यायालय ने एससीसी पैरा 17 पृष्ठ 466 में किसी अधिनियम की संवैधानिकता का न्याय करने के तरीके पर कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। इस न्यायालय ने माना कि इस अभ्यास में न्यायालय को यह करना चाहिए:

(ए) जहां तक संभव हो विवादित कानून की वैधता को बनाए रखने का प्रयास करें। यह अधिनियम को तभी रद्द कर सकता है जब इसे बनाए रखना असंभव हो;

(बी) न्यायालय को अधिनियम में खामियां निकालने या प्रारूपण में या प्रयुक्त भाषा में दोष खोजने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए;

(सी) न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि विधायिका द्वारा बनाया गया अधिनियम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है;

(डी) न्यायालय को अधिनियम को तभी रद्द करना चाहिए जब असंवैधानिकता स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से स्थापित हो;

(ई) न्यायालय को विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व को पहचानना चाहिए और इसे उचित सम्मान और आदर देना चाहिए। इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अलग कर दिया।

83. बिहार राज्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर, (1949) 2 केबी 481 में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियों पर भी विचार किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी कानून को बनाने में न्यायाधीश का काम रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। संसद की मंशा का पता लगाने का कार्य और यह (ए) न केवल कानून की भाषा से किया जाना चाहिए बल्कि (बी) उन सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करके

भी किया जाना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया (सी) और उस शरारत पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसका समाधान करना चाहिए कानून पारित किया गया था और यदि आवश्यक हो तो (डी) न्यायाधीश को लिखित शब्द को पूरक करना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को "जीवन को बल" दिया जा सके।

84. धरम दत्त 5 में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया गया था। यह निर्णय अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के उस तर्क से निपटने के लिए प्रासंगिक है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को "दो वर्ष" से घटाकर "एक वर्ष" करने और फिर आवश्यक बहुमत को 2/3 से कम करने के लिए साधारण बहुमत के बावजूद, विधायिका एक स्थानीय नेता से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रभावशाली मंत्रियों के भयानक इरादे से निर्देशित थी, जो पंचायत के प्रधान के रूप में, राज्य के मंत्री का बहुत शक्तिशाली और प्रतिस्पर्धी बन सकता था।
85. धरम दत्त (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने माना कि यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। यदि विधायिका में क्षमता है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता और उस मकसद की किसी भी जांच से कोई फायदा नहीं होगा जिसने संसद को अधिनियम पारित करने के लिए राजी किया।
86. मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात 4 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया था। लाहोटी, सीजे एससीसी पी में निर्धारित बेंच के लिए बोल रहे हैं। 562, रिपोर्ट के पैरा 39 में कहा गया है कि विधायिका संविधान में उल्लिखित लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी सहायता करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। न्यायालय विधायी प्रक्रिया में तभी हस्तक्षेप करेगा जब कानून स्पष्ट रूप से भाग III के तहत किसी नागरिक को प्रदत्त अधिकार

का उल्लंघन करता हो या जब अधिनियम विधायिका की विधायी क्षमता से परे हो। निःसंदेह न्यायालय को हमेशा कानूनों की संवैधानिकता के पक्ष में धारणा को पहचानना चाहिए और इसकी अमान्यता साबित करने का दायित्व उस पक्ष पर भारी पड़ता है जो इस पर हमला करता है।"

98. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और भानुमती के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि न्यायालय को अधिनियम को तभी रद्द करना चाहिए जब कोई अन्य संभावित तरीका न हो जिसके द्वारा अधिनियम बनाया जा सके। निरंतर। न्यायालय को अधिनियम में खामियाँ निकालने या मसौदा तैयार करने या प्रयुक्त भाषा में दोष खोजने की दृष्टि से इस पर विचार करने से बचना चाहिए। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जो अधिनियम बना है विधायिका द्वारा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है और यह व्यापक रूप से जनता के हित में है। अंत में, न्यायालय को विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व को पहचानना चाहिए और उसे उचित सम्मान और आदर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। यदि विधायिका में सक्षमता है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता और उस मकसद की किसी भी जांच से कोई फायदा नहीं होगा जिसने विधायिका को अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में उल्लिखित लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए विधायिका सबसे अच्छी स्थिति में है। न्यायालय विधायी प्रक्रिया में तभी हस्तक्षेप करेगा जब अधिनियम विधायिका की विधायी क्षमता से परे हो और यह मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन करता हो। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय को हमेशा कानूनों की संवैधानिकता के पक्ष में धारणा को पहचानना चाहिए और इसकी अमान्यता साबित करने का दायित्व उस पक्ष पर बहुत अधिक होता है जो इस पर हमला करता

है। संविधान स्वयं किसी मानक कर निर्धारण प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, सिवाय इसके कि यह निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी होनी चाहिए। चूँकि कर कानून एक आर्थिक कानून है, न्यायालय को दृष्टिकोण में न्यायिक संयम बरतना चाहिए और विधायिका को अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। राज्य विधायिका द्वारा कर कानून बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से सार्वजनिक हित है, क्योंकि राज्य को कर की आवश्यकता है, पैसा, और अंततः बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण में उपयोग किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत हित की कीमत पर सार्वजनिक हित का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।

99. यह सूचित किया गया है कि वर्तमान रिट याचिकाओं के बैच में याचिकाकर्ता इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 31.05.2016 के आदेश, डब्ल्यूपीएमएस संख्या में पारित अंतरिम आदेश का आनंद ले रहे थे। 2016 का 1500। वही अंश यहां नीचे दिया गया है:

"याचिकाकर्ता के वकील श्री डीएस पाटनी। श्री पीसी बिष्ट, उत्तराखंड राज्य / प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7 और 8 के लिए स्थायी वकील। श्री राकेश थपलियाल, प्रतिवादी संख्या 2. के वकील। श्री संजय भट्ट, प्रतिवादी संख्या के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील। 6. श्रीमती बीना पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी वकील / प्रतिवादी संख्या। 10 और 11. सुना। प्रतिवादी संख्या को नोटिस जारी करें। 9. एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं। उक्त प्रतिवादी को नोटिस तामील होने के बाद सूची बनाएं। साथ ही अंतरिम राहत अर्जी पर भी सुनवाई की। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यदि, अंततः, न्यायालय निर्णय लेता है कि याचिकाकर्ता जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो याचिकाकर्ता निश्चित रूप से इसे राज्य सरकार के पक्ष में जमा करेगा।

अंतरिम राहत आवेदन संख्या. 5226/2016 को प्रतिवादी क्रमांक को निर्देशित कर निस्तारित किया जाता है। 7 याचिकाकर्ता से जल कर की मांग की वसूली के लिए कठोर कदम न उठाएं, जो उक्त प्राधिकारी द्वारा पत्र

दिनांक 26.04.2016 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक संख्या 8) के माध्यम से जारी किया गया था। जैसा कि प्रार्थना की गई है, उत्तरदाताओं को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।"

100. इस अदालत की राय है कि ऐसा अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसलिए, रिट याचिकाओं के बैच में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए अंतरिम आदेश रद्द हो गए हैं।

101. आगे बताया गया है कि नोडल अधिकारी ने पिछले वर्षों के प्रासंगिक उपलब्ध आंकड़ों के साथ-साथ पानी के पिछले उपयोग के आधार पर याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा खींचे गए पानी और उस पर देय कर का अनंतिम मूल्यांकन किया है। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्तमान आंकड़े। इस तरह की कवायद की आवश्यकता याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा स्रोत से खींचे गए पानी से संबंधित प्रासंगिक डेटा को अस्वीकार करने के कारण उत्पन्न हुई है।

102. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष एक संकलन रखा है जिसमें दिखाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने बिजली की लागत की गणना करते समय राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जल कर को शामिल किया है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अस्वीकार कर दिया है। जो भी हो, तथ्य यह है कि चूंकि इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याचिकाकर्ताओं ने बिजली उत्पादन की लागत में जल कर को शामिल किया है या नहीं।

103. मूल्यांकन याचिकाकर्ता कंपनियों की आपत्तियों के अधीन अनंतिम रूप से किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अनंतिम मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उन्होंने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक ओर, याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक वैधता और अधिनियम की

शक्तियों को चुनौती दी है, दूसरी ओर, वे उन्हें जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। जहां तक नोटिस की वैधता का सवाल है, सबसे पहले यह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की जाने वाली आपत्तियों के अधीन एक अनंतिम मूल्यांकन है; दूसरे, इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। इस प्रकार, अनंतिम मूल्यांकन और याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए मांग नोटिस में कोई दोष नहीं जोड़ा जा सकता है।

104. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(लोकपाल सिंह, जे.)

12 फरवरी 2021.